जनादेश, जन-भावना और वित्तीय भविष्य...

धर्म के नाम पर मौत का वैश्विक व्यापार

नई उड़ान, नया क्षितिज

आयुर्वेद पर मगरूर आधुनिकता का हमला

लाईफ वर्सिटी

वर्ष- 03 अंक -08 नवम्बर 2025 मूल्य - 50 रू.

www.scgnews.in

RNI No. CHHHIN/2023/87466

Postal Regn. No. C.G./RYP DN/108/2024-26

25 साल

किस दिशा में जा रहा छत्तीसगढ़ ?

26 लाख से अधिक परिवारों को पक्की छत
पीएम आवास योजना
26 लाख किसानों को लाभ
पीएम किसान सम्मान निधि
6,691 ग्राम लाभान्वित
लगभग 70 लाख महिलाएं लाभान्वित
महतारी वंदन योजना
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
लगभग 37 लाख महिलाएं लाभान्वित
शक्तिपीठ परियोजना
29 हजार से अधिक
राज्य राजधानी क्षेत्र (SCR)
₹7.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त
इन्वेस्ट छत्तीसगढ़
13 लाख संग्राहक परिवार लाभान्वित
उद्यम क्रांति योजना
50% सब्सिडी
₹47,447 करोड़
रेलवे
जल जीवन मिशन
40 लाख
सड़क
पीएम जनमन योजना
लगभग 60 हजार परिवारों को लाभ
मोदी की गारंटी से
संवर रहा छत्तीसगढ़
संवाद- 13504/197
माननीय प्रधानमंत्री
श्री नरेन्द्र मोदी जी
के दूरदर्शी नेतृत्व में
छत्तीसगढ़ को मिल रही
नई पहचान
श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़
Visit us : /ChhattisgarhCMO /DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in

सम्पादक
नरेन्द्र कुमार पाण्डेय

प्रबंधक
हर्षित पाण्डेय

सलाहकार मण्डल

डॉ अनिल गुप्ता	रायपुर
डॉ उदयभान सिंह चौहान	रायपुर
प्रो. डॉ शुभ्रा सान्याल	नई दिल्ली
प्रो तपन मोहन्ति	ओड़िसा

छत्तीसगढ़ कार्यालय
ए-32, आम्रपाली सोसाइटी, कलर्स मॉल के पीछे, पचपेड़ी नाका
रायपुर (छ.ग.)
मो. 88171-94979

मध्यप्रदेश कार्यालय
अनामिका पाण्डेय
गोकुलधाम बेलौहान टोला,
सामान, रीवा मप्र

प्रतिनिधि

अम्बुज अग्निहोत्री	जबलपुर
संजीव पाण्डेय	भोपाल
राजेश सिंह	बिलासपुर

कानूनी सलाहकार
संजयेंदु पंड्या

परिकल्पना
रजनीकांत पाण्डेय

अंदर के पृष्ठों पर

03 जनादेश, जन-भावना और वित्तीय भविष्य का बड़ा सवाल

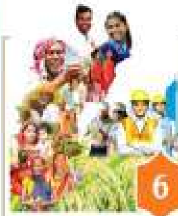

6 25 साल का सफर चार नेतृत्व, एक राज्य की बदलती पहचान

16 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नए विधानसभा भवन को राज्य को किया समर्पित

24 आधुनिक इलाज और होलिस्टिक वैलनेस—अब एक साथ

13 वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान, सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध

28 मन का युद्ध भूमि

लाल किले का ब्लास्ट	10
राज्योत्सव पर वायु सेना की..	16
नई उड़ान, नया क्षितिज	19
आयुर्वेद पर मगरूर...	23
तनाव से ट्रांसफॉर्मेशन तक	26

SCAN & PAY

UPI ID: 32994441326391 4@cnrb

लाईफ वर्सिटी के प्रचार-प्रसार में सहयोग करें।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक - नरेन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा बुरहानी प्रिंटर्स, सत्ती बाजार रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित एवं 6, विकास विहार कालोनी, साईं वाटिका,जोरातालाब के पास रायपुरा, रायपुर (छ.ग.) से प्रकाशित। संपादक- नरेन्द्र कुमार पाण्डेय, मो. 88171-94979
E-mail : scgnewsraipur@gmail.com | www.scgnews.in

रायपुर से उठी भारत की नई आवाज़

नरेन्द्र कुमार पाण्डेय
सम्पादक

छत्तीसगढ़... एक राज्य जो कभी संघर्ष की मिट्टी से उठा था – और आज उसी मिट्टी से 'शांति शिखर' जैसी इमारत खड़ी है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर आए... सवाल ये है कि इस दौरे की तस्वीर में कौन-सा भारत नज़र आता है – आध्यात्मिक भारत, या इन्फ्रास्ट्रक्चर वाला भारत... या दोनों का नया संगम?

रायपुर एयरपोर्ट से लेकर नवा रायपुर तक... प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो हुआ । सड़कों पर भीड़ थी, हाथ हिलाते लोग थे, और हवा में था एक उत्साह। लेकिन क्या ये उत्साह सिर्फ प्रधानमंत्री की मौजूदगी का था? या फिर उस 'नए छत्तीसगढ़' का, जो अपनी 25वीं सालगिरह पर खुद को नए चेहरे के साथ देखना चाहता है?

दिल की बात... लेकिन इस बार दिल के मरीजों के साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने 2500 बच्चों से बात की – वो बच्चे जिनका हृदय कभी कमजोर था, लेकिन आज उनमें 'नया जीवन' धड़क रहा है। यानी, 'दिल की बात' अब केवल रेडियो पर नहीं, अस्पताल के वार्डों में भी सुनाई दी।

और फिर – 'शांति शिखर'। नवा रायपुर के सेक्टर-20 में खड़ा ये भवन सिर्फ पत्थर और बीम का जोड़ नहीं है... ये भारत के उस दर्शन का प्रतीक है, जहां विकास और ध्यान एक ही दिशा में चलते हैं।

150 फीट चौड़ा, 225 फीट लंबा, पिंक स्टोन से सजा... सात साल की तपस्या, हजारों लोगों का सहयोग, और एक भाव – 'शांति ही शक्ति है। प्रधानमंत्री ने जब इसका लोकार्पण किया, तो दरअसल उन्होंने सिर्फ एक इमारत नहीं खोली – उन्होंने एक विचार को सार्वजनिक किया... कि आध्यात्मिकता अब भारत की सॉफ्ट पावर नहीं, बल्कि हार्ड रियलिटी बन चुकी है।

अब ज़रा इस तस्वीर को देखिए –

नवा रायपुर का नया विधानसभा भवन। 273 करोड़ की लागत, 20 हेक्टेयर में फैला परिसर, और राष्ट्रपति भवन जैसी भव्यता। लेकिन अंतर क्या है? वहां दिल्ली की सत्ता है – यहां छत्तीसगढ़ की अस्मिता।

बस्तर और सरगुजा की कला से सजा यह भवन बताता है कि छत्तीसगढ़ अब 'केंद्र की छाया' नहीं, अपनी धूप में जीना चाहता है। और इसी बीच... रायपुर रेलवे स्टेशन पर गूंज उठा – 'अरपा-पैरी के धार... जय हो छत्तीसगढ़ मईया!' यह सिर्फ राज्य गीत नहीं था, यह जवाब था उस 'सांस्कृतिक विस्थापन' को, जो कुछ दिन पहले छठ गीत बजने पर उठा था। यानी अब छत्तीसगढ़ कह रहा है – 'हम भी हैं, हमारी भी आवाज़ है।

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा के सामने जब प्रधानमंत्री ने 'एक पेड़ मां के नाम' लगाया – तो वो पल प्रतीक बन गया। राजनीति में श्रद्धा, शासन में संस्कार... और विकास में भावना।

सवाल यह नहीं कि छत्तीसगढ़ कितना बदला है, सवाल यह है कि अब छत्तीसगढ़ खुद को किस रूप में देखना चाहता है – उद्योग की भूमि, संस्कृति की मिट्टी या शांति की राजधानी?

और शायद इसी सवाल का जवाब आज रायपुर ने दिया है... जब एक ओर ब्रह्माकुमारीज़ का शांति शिखर खड़ा हुआ – और दूसरी ओर विधानसभा का भव्य द्वार खुला। यानी भारत का नया चेहरा – जहां शासन और साधना एक साथ खड़े हैं। कहानी छत्तीसगढ़ की है, लेकिन संदेश पूरे भारत के लिए है – शांति ही विकास है, और विकास तभी टिकेगा, जब उसकी जड़ में शांति होगी।

जनादेश, जन-भावना और वित्तीय भविष्य का बड़ा सवाल

2025 के बिहार विधानसभा चुनावों ने भारतीय राजनीति के परिदृश्य में एक ऐसा क्रेशेंडो रचा है, जो न केवल वर्तमान सत्ता-समीकरण को प्रभावित करेगा बल्कि आने वाले वर्षों की राष्ट्रीय राजनीति की दिशा भी निर्धारित करेगा। इसे मात्र 'एक चुनाव' कहना अन्याय होगा—यह एक राजनीतिक आंदोलन, एक सामाजिक बदलाव, और एक मतदाता की नई चेतना का जनादेश है।

जनादेश जिसने 10 साल की राजनीति की पटकथा लिख दी

सबसे पहले तथ्य—यह जनादेश केवल सीटों का योग नहीं, बल्कि मानसिकता का माप है। यह उस बदलाव का संकेत है जिसमें जनता ने न सिर्फ नेताओं को, बल्कि राजनीति के पारंपरिक ढांचे को भी बदल दिया।

तीन ऐतिहासिक घटनाएँ इस चुनाव को विशिष्ट बनाती हैं—

- **90% तक का स्ट्राइक रेट—भारतीय इतिहास में दुर्लभ**

छोटे दलों का यह प्रदर्शन बताता है कि मतदाता पूरी एकतरफा लहर में थे।

- **35 साल पुरानी जाति-आधारित राजनीति का आधिकारिक पटाक्षेप**

MY (Muslim–Yadav) समीकरण, जो लालू राजनीति का मेरुदंड था, पहली बार ढह गया।

- **महिला मतदाताओं का रिकॉर्ड टर्नआउट—निर्णय-निर्धारक शक्ति के रूप में उभार**

यह लहर किसी पार्टी की नहीं थी—एक सामाजिक समूह की थी।

NDA की रणनीति—विकास कथा + महिला सशक्तिकरण + नेतृत्व की विश्वसनीयता

छत्तीसगढ़ BJP अध्यक्ष किरणदेव सिंह का बयान इस जनादेश के सार को समझाता है— 'बिहार ने डबल इंजन सरकार पर भरोसा किया है।'

एनडीए का नैरेटिव तीन स्तंभों पर टिका था—

- **विकास**
- **सुशासन**
- **भयमुक्त प्रशासन**

लेकिन असली गेम-चेंजर था— महिला-केंद्रित योजनाओं का 'लॉन्ग-टर्म सोशल कैपिटल'

नीतीश कुमार के शिक्षा-साइकिल-गैस-आवास मॉडल ने महिलाओं के मन में 'विश्वास' की एक स्थायी परत बनाई थी।

इस बार इसी विश्वास को प्रधानमंत्री मोदी

के राष्ट्रीय नेतृत्व ने और विस्तार दिया।

विपक्ष के आरोप–चुनाव की वैधता पर बड़ा प्रश्न या राजनीतिक असहजता?

छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला कहते हैं– 'यह लोकतंत्र की हत्या है।'

भूपेश बघेल का तंज– 'मुख्य चुनाव आयुक्त को बधाई।'

आरोप तीन प्रमुख बिंदुओं पर केंद्रित रहे–

- MCC के दौरान 10,000 रुपए महिला खातों में भेजना
- मतदाता सूची में भारी फेरबदल
- लाखों वोट हटाने व जोड़ने का आरोप

लेकिन जब आँकड़ों को खोलकर देखते हैं, तो चुनाव का असली चमत्कार सामने आता है–

यह बताता है–

- बिहार ने किसी 'एक सामाजिक ब्लॉक' को नहीं, बल्कि 'पूरे NDA गठबंधन को सामूहिक रूप से' स्वीकार किया।

MY समीकरण का पतन–बिहार के सामाजिक परिवर्तन की घोषणा

35 वर्षों से लालू यादव की राजनीति जिस आधार पर खड़ी थी, वह पहली बार हिल गया। मुस्लिम मतदाताओं का बड़ा हिस्सा अब 'सुरक्षा + स्थिरता + कल्याण' की ओर झुक गया है। युवा वर्ग जाति–नारे से थक चुका था। महिलाओं ने एक नई सामाजिक–अर्थव्यवस्था का निर्माण कर दिया है, जहाँ भावनाएँ नहीं, आज की जरूरतें प्राथमिकता हैं।

यह वही क्षण है जब बिहार ने कहा–

'जाति पुरानी हो चुकी है, अब शासन और विकास से चुनाव जीते जाएंगे।'

वोट प्रतिशत बनाम सीटें–कहानी बदलने वाला डेटा

पार्टी	वोट स्विंग	सीटों में बदलाव
RJD	–0.35%	–50 सीटें
BJP	+1%	+25-30 सीटें
JDU	+3%	+40 सीटें
LJP, HAM, RLSP	मामूली वोट, पर 90% स्ट्राइक रेट	

क्यों उठी इतनी बड़ी लहर?

बिहार का ग्रामीण मतदाता संवेदनशील है, परंतु मूर्ख नहीं।

इस चुनाव में उसकी प्राथमिकताएँ क्रिस्टल- क्लीयर थीं–

- सुरक्षा
- रोजगार
- महिलाओं की भागीदारी
- कल्याणकारी योजनाओं की विश्वसनीयता
- राष्ट्रीय नेतृत्व की स्थिरता

ग्रामीण मतदाता ने नेतृत्व को विकल्पों के तराजू में तौला और कहा–

'मोदी–नीतीश का कॉम्बिनेशन स्थिरता भी देता है और विश्वसनीयता भी।'

अब आते हैं असली सवाल पर– बिहार की आर्थिक सेहत

बिहार की आर्थिक स्थिति किसी भी निष्पक्ष विश्लेषण में चिंता का विषय बनती है।

कर्ज का इतिहास

2005 — रू. 42,500 करोड़
2025 — रू.3.19 लाख करोड़

यानी 8 गुना वृद्धि

➔ प्रति व्यक्ति कर्ज–24,000 रुपए से अधिक

बजट बनाम कर्ज

➔ बजट- रू. 3.16 लाख करोड़
➔ कर्ज- रू. 3.19 लाख करोड़

यानी राज्य MARGIN पर नहीं–NEGATIVE पर चल रहा है।

चुनावी फ्रीबीज : अर्थव्यवस्था की रीढ़ पर भार

5 प्रमुख घोषणाएँ जो बिहार की वित्तीय संरचना पर भारी पड़ सकती हैं-

➔ 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए
➔ 125 यूनिट फ्री बिजली
➔ पेंशन 400 से 1100
➔ बेरोजगारों को भत्ता
➔ पंचायत प्रतिनिधियों का वेतन वृद्धि

इन सबका वार्षिक भार

➔ 10,000 करोड़ रुपए से अधिक

प्रश्न यह है– **क्या बिहार इसे अफोर्ड कर सकता है?**

जवाब है–**नहीं।**

कारण

- बिहार की अर्थव्यवस्था अभी रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रही
- इंडस्ट्री न के बराबर
- प्राइवेट सेक्टर लगभग अनुपस्थित
- 80% रोजगार सरकारी ढांचे पर
- विशाल गरीब आबादी (34% परिवार 6,000/माह से कम आय)

फ्रीबीज का असर यह होगा—

- विकास योजनाएँ कटेंगी
- कर्ज बढ़ेगा
- राज्य वित्तीय संकट में जाएगा

दिल्ली, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र, कर्नाटक—इन सभी राज्यों की कहानियाँ चेतावनी देती हैं कि फ्रीबीज मॉडल टिकाऊ नहीं होता।

बिहार को चाहिए 'वेलफेयर मॉडल', नहीं 'फ्रीबीज मॉडल'

सोशल सिक्योरिटी जरूरी है—

पर फ्रीबीज—अर्थव्यवस्था को ICU में ले जाते हैं। यह चुनाव जीतने का तरीका हो सकता है, पर राज्य चलाने का नहीं।

बिहार को आज जिन 3 चीज़ों की जरूरत है—

- बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री
- युवाओं के लिए रोजगार
- कृषि और MSME आधारित अर्थव्यवस्था

राष्ट्रीय राजनीति पर असर–2029 की राह यहीं से निकलेगी

इस चुनाव ने कुछ स्पष्ट संकेत दिए हैं—

मोदी को चुनावी रूप से चुनौती देना अब बहुत मुश्किल

2024 की गिरावट के बाद इस जनादेश ने एक 'रीसेट' मोड स्थापित किया है।

बंगाल और तमिलनाडु NDA का अगला टारगेट

दोनों राज्यों की सरकारें दबाव में आएंगी।

विपक्ष के लिए 'रेड अलर्ट'

उनके पास अभी भी—

- एजेंडा नहीं
- संयुक्त नेतृत्व नहीं
- जमीनी पकड़ नहीं
- और ना ही विकास मॉडल का विकल्प

महागठबंधन राजनीति का पतन

'सब एकजुट होकर भी NDA का मुकाबला नहीं कर सके'— यह संदेश राष्ट्रीय राजनीति को बदल देगा।

क्या बिहार ने एक नया युग शुरू किया है?

इस चुनाव को सिर्फ परिणाम के रूप में नहीं, बल्कि एक सामाजिक दस्तावेज के रूप में समझना चाहिए।

यह चुनाव बताता है—

- महिलाएँ अब राजनीति तय करती हैं
- जाति का युग खत्म, शासन का युग शुरू
- जनादेश अब स्थिरता और नेतृत्व पर मिलता है
- राज्य की वित्तीय सेहत चुनावी राजनीति से बड़ी है

और सबसे जरूरी—

बिहार भारत की राजनीति का लिटमस टेस्ट है।

यहाँ जो होता है, वह देश की राजनीति का अगला अध्याय लिखता है।

तो आखिर सवाल वही—

क्या बिहार के इस जनादेश ने भारत में एक नया राजनीतिक युग शुरू कर दिया है?

या विपक्ष के सवाल इस तेज़ हवा में खो जाएँगे?

जवाब आने वाले वर्षों में मिलेगा—

लेकिन इतना तय है कि

2025 का बिहार चुनाव इतिहास में एक मील का पत्थर लिखा जाएगा।

25 साल का सफर
चार नेतृत्व
एक राज्य की बदलती पहचान

1 नवंबर 2000 को जब मध्यप्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ एक नए राज्य के रूप में जन्मा, तब यह सवाल बड़ा था कि—

क्या यह प्रदेश अपने अपार संसाधनों के बावजूद विकास का कोई स्थायी मॉडल स्थापित कर पाएगा? क्योंकि देश के कई नए राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ को भी विरासत में कमजोर ढांचा, असमान विकास, नक्सल प्रभावित भूभाग और संस्थागत कमी मिली थी। लेकिन यह कहानी इतनी सीधी भी नहीं।

अगले 25 वर्षों में यहाँ चार अलग-अलग मुख्यमंत्री आए- जिन्होंने अपने-अपने दौर में राज्य को पूरी तरह नई दिशा और प्राथमिकताएँ दीं।

- **अजीत जोगी** - नींव और प्रशासनिक ढाँचा तैयार करने वाला दौर
- **डॉ. रमन सिंह**- स्थिरता, योजनाओं की गहराई और सुशासन का विस्तार
- **भूपेश बघेल**- किसान, परंपरा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था केंद्रित 'छत्तीसगढ़ मॉडल'
- **विष्णुदेव साय** (वर्तमान सरकार) - इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, निवेश और तेज आर्थिक सुधार

इन चार युगों ने मिलकर छत्तीसगढ़ की पहचान को गढ़ा है।

वर्तमान सरकार (विष्णु सरकार)

तेज इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योग-आधारित नया मॉडल

दो वर्ष के भीतर वर्तमान सरकार ने यह स्पष्ट संकेत दिया कि छत्तीसगढ़ अब परिवहन, उद्योग, निवेश और आर्थिक सुधारों पर आधारित ग्रोथ पाथ अपनाने की दिशा में चल पड़ा है।

1. परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी - 31,000 करोड़ की परियोजनाएँ

सिर्फ दो वर्षों में राज्य सरकार ने 31,000 करोड़ रुपये की सड़क, पुल और राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी। यह राज्य के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पुश माना जा रहा है।

राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार, ग्रामीण संपर्क सड़कों में तेजी, लॉजिस्टिक्स सुधार, औद्योगिक क्षेत्रों के लिए एक्सेस रोड निर्माण। यह संकेत है कि सरकार आने वाले वर्षों में इंडस्ट्री-ड्रिवन इकोनॉमी को मजबूती देना चाहती है।

2. चार शहरों में आई-बस सेवा, अंबिकापुर से हवाई सेवा

सार्वजनिक परिवहन में यह सबसे बड़ा परिवर्तन माना जा सकता है— रायपुर , बिलासपुर, दुर्ग , रायगढ़। इन चार शहरों में आई-बस (इंटेलिजेंट बस सेवा) लागू करने का निर्णय लिया गया। यह शहरी आवागमन में क्रांतिकारी सुधार ला सकता है।

साथ ही अंबिकापुर से हवाई सेवा की शुरुआत ने सरगुजा क्षेत्र को कनेक्टिविटी को नई दिशा दी है।

3. नई औद्योगिक नीति – पर्यटन और MSME को बढ़ावा

1 नवंबर से लागू की गई नई औद्योगिक नीति में उद्योगों के साथ-साथ पर्यटन, एमएसएमई, फूड प्रोसेसिंग और सर्विस सेक्टर को विशेष प्रोत्साहन दिया गया है। सिंगल विंडो सिस्टम को सरल किया गया। निवेशकों के लिए विशेष पैकेज। जिला स्तर पर MSME क्लस्टर के विकास, पर्यटन में निजी निवेश आकर्षित करने के नए प्रावधान। इसके साथ ही राज्य आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। जिसका उद्देश्य है — 'निवेश को त्वरित गति देना और रोजगार संभावनाओं को बढ़ाना।'

4. किसान उन्नत योजना- धान खरीदी में ऐतिहासिक भुगतान

सरकार ने अपने वादे के अनुसार—प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी, रू. 3100 प्रति क्विंटल का भुगतान, दो वर्षों का बकाया बोनस लौटाया। कुल मिलाकर लाखों किसानों को सीधा आर्थिक लाभ मिला।

5. महतारी वंदन योजना - महिलाओं में आर्थिक विश्वास

यह योजना वाकई गेम-चेंजर साबित हुई है। हर महिला के खाते में रू.1000 प्रति माह। लाखों परिवारों में सीधा वित्तीय सहायता। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा। अब तक सरकार कुल 10 किस्तें जारी कर चुकी है।

6. आवास और स्वास्थ्य - प्राथमिकता में समाज का अंतिम व्यक्ति

- पीएम आवास ग्रामीण के तहत 8.46 लाख आवास।
- चार लाख से अधिक परिवारों को 'छत' मिल चुकी है।
- हाउसिंग बोर्ड द्वारा 50,000 नए घरों का लक्ष्य
- बिलासपुर में 200 करोड़ का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल
- रायपुर मेडिकल कॉलेज की नई बिल्डिंग के टेंडर
- यहाँ तक कि विपक्ष ने भी स्वास्थ्य संरचना के इस विस्तार की सराहना की।
- रामलला दर्शन योजना – धार्मिक पर्यटन को नई दिशा
- अयोध्या यात्रा की सरकारी व्यवस्था
- मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का पुनरारंभ
- बुजुर्गों और श्रद्धालुओं के लिए विशेष प्रावधान। यह सांस्कृतिक पर्यटन को गति देता है।

विष्णु सरकार का फोकस साफ है–

इन्फ्रास्ट्रक्चर + निवेश + महिला सशक्तिकरण + किसान सम्मान -नया छत्तीसगढ़ विकास मॉडल।

भूपेश बघेल
किसान-केन्द्रित और 'छत्तीसगढ़ी अस्मिता' पर आधारित शासन मॉडल

2018-2023 का कालखंड छत्तीसगढ़ की राजनीति में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्थानीय संस्कृति को केंद्र में रखने वाला दौर माना जाता है।

1. पुरानी पेंशन बहाली (OPS) – करोड़ों परिवारों को सीधी राहत

मार्च 2022 में OPS लागू होने के बाद—10% वेतन कटौती खत्म। पेंशन अंतिम वेतन और महंगाई भत्ते के आधार पर। सरकारी कर्मचारियों का सरकार पर भरोसा बढ़ा। छत्तीसगढ़ उन राज्यों में शामिल हुआ जहाँ कर्मचारियों ने इसे बड़ी उपलब्धि माना।

2. राजीव गांधी किसान न्याय योजना - रु.9000 प्रति एकड़

यह राज्य की सबसे प्रभावी किसान-केंद्रित योजनाओं में से एक रही।

- प्रति एकड़ रू.9000 सब्सिडी
- पुराने किसान दोबारा खेती में लौटे
- युवाओं में खेती के प्रति रुचि बढ़ी
- ग्रामीण बाजारों में नकदी प्रवाह बढ़ा
- यह योजना आर्थिक रूप से बेहद प्रभावशाली रही।

3. बिजली बिल हाफ योजना - 42 लाख उपभोक्ताओं को लाभ

- 400 यूनिट तक 50% छूट
- गरीब परिवारों को 30 यूनिट मुफ्त बिजली
- लगभग रू.2500 करोड़ की राहत दी गई

हालाँकि सरकार बदलने के बाद इसमें बदलाव आया।

4. इंडस्ट्रियल पार्क रीपा योजना -ग्रामीण उद्यमिता की नई राह

- सिलाई, लोहार, मसाला, जूस जैसे छोटे व्यवसायों को प्रोत्साहन
- इन उद्यमों को बिजली, पानी, शौचालय जैसी सुविधाएँ
- ग्रामीण उद्योगों में रोजगार सृजन
- यह 'ग्रामीण स्टार्टअप मॉडल' की तरह देखा गया।

5. गोधन न्याय योजना- गोबर और गोमूत्र आधारित आर्थिक नवाचार

20 जुलाई 2020 को शुरू इस योजना ने राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा बटोरी—

- 2 प्रति किलो गोबर
- 4 प्रति लीटर गोमूत्र

- ग्रामीण क्षेत्रों में वैकल्पिक आमदनी
- स्कॉच गोल्ड व e-Governance अवार्ड
- यह छत्तीसगढ़ का सबसे नवाचारी ग्रामीण मॉडल साबित हुआ।

6. हाट-बाजार क्लिनिक - स्वास्थ्य सेवाओं का विकेंद्रीकरण

- 2 अक्टूबर 2019 को शुरुआत
- साप्ताहिक हाट-बाजारों में डॉक्टर व स्वास्थ्य सेवाएँ
- आदिवासी क्षेत्रों में अत्यधिक प्रभाव

यह योजना जमीनी स्तर पर ग्रामीणों से सीधा जुड़ाव का उदाहरण मानी गई।

बघेल सरकार

किसान + ग्रामीण अर्थव्यवस्था + परंपरागत समाज + छोटे उद्योग = छत्तीसगढ़ी मॉडल।

डॉ. रमन सिंह – सुशासन और स्थिर शासन का स्वर्णकाल (2003-2018)

डॉ. रमन सिंह का 15 साल का कार्यकाल, छत्तीसगढ़ की राजनीति का 'सबसे स्थिर और संस्थागत' काल माना जाता है।

1. धान बोनस और समर्थन मूल्य नेटवर्क - किसानों की रीढ़ मजबूत

- धान खरीदी केंद्रों का विस्तृत नेटवर्क
- बोनस राशि से किसानों की आमदनी में भारी वृद्धि
- राज्य की पहचान 'धान का कटोरा' के रूप में और मजबूत हुई

यह उनकी सबसे प्रभावी और लोकप्रिय नीतियों में से एक थी।

2. नक्सल क्षेत्रों में विकास – सड़कों, स्कूलों और कैंपों का विस्तार

- बस्तर में सड़क निर्माण
- पुलिस कैंपों की स्थापना
- मोबाइल नेटवर्क और स्वास्थ्य सेवाएँ
- स्कूलों का पुनर्संचालन
- यह प्रदेश के सुरक्षा ढांचे में बड़ा मोड़ माना जाता है।

3. सड़क और बिजली – ग्रामीण कनेक्टिविटी की रीढ़

- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना
- बिजली वितरण सुधार कार्यक्रम
- लगभग हर गाँव तक बिजली पहुँचाना
- इससे गांव-शहर का अंतर घटा।

4. मध्याह्न भोजन और पोषण योजनाएँ

- सुपोषण अभियान
- मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना
- मिड-डे मील में सुधार, इससे बाल-स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार हुआ।

5. सार्वजनिक वितरण प्रणाली - 'चावल वाला बाबा' की पहचान

- छत्तीसगढ़ की PDS देशभर में 'मॉडल' बनी– पारदर्शिता, तकनीक आधारित वितरण, भ्रष्टाचार लगभग समाप्त> कई राज्यों ने यह मॉडल अपनाया।

6. लोकवाणी और जनदर्शन - जनता से प्रत्यक्ष संवाद

- रेडियो के माध्यम से संवाद
- हर सप्ताह जनदर्शन
- शिकायतों का समाधान

  यह प्रशासन को जनता से जोड़ने का सफल मॉडल था।

7. औद्योगिक विकास - रायगढ़, दुर्ग, कोरबा का विस्तार

- बड़े उद्योगों की स्थापना
- रोजगार के अवसर
- खनिज आधारित उद्योगों का विकास
- छत्तीसगढ़ को 'इंडस्ट्रियल हब' बनाने की दिशा यही दौर तय करता है।

डॉ. रमन सिंह

स्थिरता + सुशासन + कल्याण योजनाएँ + आधारभूत ढाँचा = छत्तीसगढ़ का स्वर्णकाल ।

अजीत जोगी
नींव रखने वाला प्रारंभिक युग (2000-2003)

राज्य गठन के बाद चुनौतियाँ अधिक थीं और संसाधन सीमित। इन परिस्थितियों में जोगी सरकार ने संस्थाओं, कानूनों और बुनियादी ढांचे का ढांचा खड़ा किया।

1. पर्यावरण, जल संरक्षण और हरित छत्तीसगढ़

- वृक्षारोपण अभियान
- नर्मदा-छत्तीसगढ़ जल योजना
- लघु सिंचाई परियोजनाओं का विस्तार। यह राज्य के प्रारंभिक जल प्रबंधन की नींव थी।

2. जनजातीय और गरीब कल्याण की नींव

- वन अधिकार, ग्राम सभा अधिकार
- वन उपज समर्थन मूल्य की शुरुआत
- गरीबी उन्मूलन और आवास योजनाएँ
- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। छत्तीसगढ़ की सामाजिक संरचना को यह दिशा देने वाला दौर था।

3. शिक्षा और स्वास्थ्य का विस्तार

- नए स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना
- इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ का विस्तार
- जिला अस्पतालों के सुधारीकरण
- स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाओं का प्रारूप

4. औद्योगिक नीति 2001 – उद्योगों के लिए पहला मार्ग

- सिंगल विंडो सिस्टम
- उद्योगों के लिए प्रोत्साहन
- रायगढ़, कोरबा, रायपुर में उद्योगों की शुरुआत

अजीत जोगी

संस्थागत ढांचा + बुनियादी नींव + सामाजिक न्याय = प्रारंभिक छत्तीसगढ़।

छत्तीसगढ़ का भविष्य किस दिशा में ?

चार मुख्यमंत्री, चार विकास मॉडल, चार अलग-अलग प्राथमिकताएँ–

लेकिन इन सभी का एक साझा लक्ष्य था-

'छत्तीसगढ़ को विकास, स्थिरता और सामाजिक न्याय के साथ आगे ले जाना।'

अब राज्य किस दिशा में आगे बढ़ रहा है?

क्या नई औद्योगिक नीति रोजगार का नया अध्याय खोलेगी?

क्या धान-आधारित अर्थव्यवस्था से उद्योग-आधारित अर्थव्यवस्था की ओर वास्तविक बदलाव होगा?

क्या नक्सलवाद आने वाले वर्षों में निर्णायक रूप से समाप्त हो सकेगा?

क्या कल्याण योजनाएँ वित्तीय संतुलन बनाए रख पाएँगी?

और क्या छत्तीसगढ़ आने वाले दशक में देश की 'उभरती अर्थव्यवस्था' बन पाएगा?

इन सवालों के जवाब आने वाला समय देगा।

लेकिन एक बात निश्चित है–

छत्तीसगढ़ का आज उन 25 वर्षों की राजनीतिक इच्छाशक्ति, निर्णय क्षमता और विकास दृष्टि का परिणाम है, जिसे चार अलग-अलग नेतृत्वों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के साथ गढ़ा है।

लाल किले का ब्लास्ट

धर्म के नाम पर मौत का वैश्विक व्यापार

दिल्ली के लाल किले के पास हुआ ताज़ा ब्लास्ट सिर्फ एक आतंकी वारदात नहीं, बल्कि आधुनिक मानवता के चेहरे पर पड़ा वह करारा तमाचा है, जो यह याद दिलाता है कि विज्ञान, तकनीक और लोकतंत्र की सैकड़ों साल की प्रगति—धर्म की दुकानों के सामने आज भी असहाय खड़ी है।

21वीं सदी के सबसे बड़े विरोधाभास का नाम है—धार्मिक कट्टरता का पुनर्जन्म।

धर्म बनाम विज्ञान - एक पुरातन लड़ाई का आधुनिक चेहरा

एक तरफ विज्ञान है—जिसने पिछले 300-400 वर्षों में मानव को वह जीवन दिया, जिसकी कल्पना तक हमारे पूर्वज नहीं कर सकते थे। दूसरी तरफ धर्म का वह पक्ष है जो अभी भी लोगों को 'मर जाओ, मार डालो, तभी धर्म बचेगा' जैसे ज़हरीले सपने दिखा रहा है। लाल किले के आसपास हुआ विस्फोट इसका ताज़ा उदाहरण है—जहाँ मेडिकल पढ़ने वाले समझदार युवा इस झूठे नैरेटिव के शिकार बने कि 'जान से बड़ा धर्म है'।

पर क्या सच में? क्या किसी भी धर्मग्रंथ ने यह कहा है कि अनपढ़ गुरु पढ़े-लिखों की सोच को कुचल दें?

धरती, दौलत और औरत से ज्यादा खून धर्म ने बहवाया

इतिहास गवाह है—राजनीतियों, साम्राज्यों, ज़मीन-जोरू-जायदाद ने इतना खून नहीं बहाया जितना धर्म के झंडे तले दुनिया नहाई है। कभी क्रूसेड में, कभी जिहाद में, कभी धर्म-युद्धों में, कभी मज़हबी पवित्रता के नाम पर।

असल सच्चाई यह है कि जमीन-जोरू-ज़र सिर्फ बहाने थे, असली फायदा हमेशा धर्म के ठेकेदारों ने उठाया— आज भी उठा रहे हैं। आधुनिक शिक्षा भी धर्म-व्यापारियों के आगे हार रही है।

सबसे खतरनाक बात यह है कि साइंस पढ़ने वाले, मेडिकल और इंजीनियरिंग के छात्र भी कट्टर संगठनों द्वारा बहुत आसानी से फंस जा रहे हैं। वे विस्फोटक इकट्ठा करते हैं, पैसे जमा करते हैं, और फिर अपने ही परिवारों को उम्रभर की शर्म और सज़ा में धकेल कर धर्मगुरुओं के लिए 'बलिदान' बन जाते हैं। यह धार्मिक चरमपंथ की सबसे भयावह उपलब्धि है— पढ़ा-लिखा युवा भी विवेक खो बैठता है।

> “दिल्ली के लाल किले के पास हुआ ताज़ा ब्लास्ट सिर्फ एक आतंकी वारदात नहीं, बल्कि आधुनिक मानवता के चेहरे पर पड़ा वह करारा तमाचा है, जो यह याद दिलाता है कि विज्ञान, तकनीक और लोकतंत्र की सैकड़ों साल की प्रगति–धर्म की दुकानों के सामने आज भी असहाय खड़ी है।”

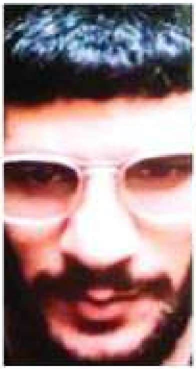

दिल्ली और इस्लामाबाद—दो शहर, एक ही कहानी

लाल किले के विस्फोट के अगले ही दिन इस्लामाबाद में आत्मघाती हमला हुआ।

दोनों देशों के राजनीतिक झगड़े अलग हो सकते हैं,लेकिन धर्म की आड़ में पाला गया कट्टरपंथ—सीमा नहीं मानता।

इन हमलों में न कोई हिंदू है, न मुसलमान, न भारतीय, न पाकिस्तानी। इनका बस एक ही नाम है—धर्मिक आतंक। इनकी एक ही पहचान है—मौत का कारोबार। जब दुनिया फल-फूल रही थी, धर्म फिर से हावी हो गया। यूरोप कभी धार्मिक युद्धों में पिसता रहा। फिर विज्ञान और लोकतंत्र ने वहां जान फूंकी। लेकिन आज, अरब दुनिया अपने कट्टरपंथियों को यूरोप की गलियों में उतार रही है, अमेरिका में चर्च राजनीति की कमान थामने की कोशिश कर रहा है, भारत में हर गली में नए-नए धर्म-शहर और गुरु-बाज़ार उग रहे हैं। धर्म की नई दुकानें—पुरानी नफरतों के लिए आधुनिक विज्ञापन चला रही हैं।

धर्म की दुकानों का असली एजेंडा-सत्ता, पैसा और भीड़

इन दुकानों को न आपकी शांति से मतलब है- न आपकी सुरक्षा से, न आपके भविष्य से। उन्हें सिर्फ उतना चाहिए कि- हर सप्ताह भीड़ जुटे, चढ़ावा बढ़े, भक्त दूसरे समुदाय से नफरत करें,और उनके 'धर्म-साम्राज्य' का विस्तार होता रहे। बाकी सब—जनता की हानि में लिखा जाता है।

आज का युवा सबसे बड़ा शिकार

आज दुनिया का हर कट्टर संगठन जानता है कि युवा मन सबसे तेज़ पकता है और सबसे आसानी से मोड़ा जा सकता है। सोशल मीडिया इसका सबसे प्रभावी टूल है। धर्म के प्रचारक युवा के भीतर झूठा guilt भरते हैं—

अगर तुमने धर्म के लिए जान नहीं दी तो तुम अधूरे हो। और फिर identity बदल देते हैं— छात्र से 'योद्धा'

डॉक्टर से 'रक्षक'

इंजीनियर से 'सैनिक'।

यह मनोविज्ञानिक है, जो किसी आतंकवादी प्रशिक्षण से भी ज्यादा खतरनाक है। दुनिया आज जितनी सुरक्षित है—धर्म की वजह से नहीं यह बहुत सीधा सच है—आज का मानव सुरक्षित है क्योंकि विज्ञान ने उसे सुरक्षा दी।

- दवाएं विज्ञान ने बनाईं
- अस्पताल विज्ञान ने बनाए
- पुल, सड़कें, पक्के घर तकनीक ने दिए
- कानून, अधिकार, मताधिकार लोकतंत्र ने दिया
- तूफानों, महामारी, अकाल—सभी से विज्ञान ने बचाया

धर्म ने क्या किया?

मनुष्य को बांटा। लड़ा दिया। डराया।

और फिर कहा—'मेरा आश्रय लो।'

धर्म आज मनुष्य को फिर से इतिहास की अंधेरी गलियों में धकेल रहा है

कट्टरपंथ चाहे किसी भी भाषा में बोले—उसका लक्ष्य एक ही है-

विज्ञान की रोशनी बुझाओ और अंधविश्वास का रास्ता दिखाओ।

लाल किले का विस्फोट इसी अंधेरे की घोषणा है।

अंतिम सवाल—जिसका जवाब हमें देना ही होगा- क्या हम विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र और मानवता की दिशा में आगे बढ़ेंगे या धर्म की दुकानों के हाथ में अपनी चेतना गिरवी रख देंगे? क्या हम उस युवा को बचाएँगे जो मेडिकल की किताबें छोड़कर डिटोनेटर उठाने लगा है? क्या हम उस समाज को बचाएँगे जो सोशल मीडिया की धार्मिक आग में रोज़-रोज़ झुलस रहा है? या फिर हम भीड़ का हिस्सा बनकर चुप खड़े रहेंगे?

इतिहास बता रहा है—

चुप रहना, पक्ष लेने जैसा ही है।

धर्म की दुकानों के पास भीड़ है,

लेकिन विज्ञान, तर्क और मानवता के पास भविष्य है। और यही भविष्य हमें चुनना होगा।

रेल सुरक्षा की पोल खोलती एक टक्कर

बिलासपुर ट्रेन हादसा हुआ... रिपोर्ट आई... और फिर वही निष्कर्ष — लोको पायलट दोषी!

फिर वही सवाल —हादसा कैसे हुआ, कौन है ज़िम्मेदार ? मगर उससे बड़ा सवाल क्या रेलवे की हर जांच... सिर्फ एक ही पटरी पर चलती है ?

क्या हर बार वही कहानी दोहराई जाती है — जैसे बिलासपुर केस में कहा गया .... लोको पायलट दोषी ? या फिर इस बार कुछ और सच दबा दिया गया है ? सवाल अब सिर्फ हादसे का नहीं... सिस्टम की सेफ्टी का है।

4 नवंबर... छत्तीसगढ़ का गतौरा-बिलासपुर सेक्शन। मेमू ट्रेन... और सामने मालगाड़ी। टक्कर इतनी ज़बरदस्त कि डिब्बे पटरी से उतर गए। रेलवे की प्राथमिक रिपोर्ट आई — कारण बताया गया, लोको पायलट विद्यासागर का सिग्नल ओवरशूट। यानि... हादसे की जिम्मेदारी — सीधे-सीधे चालक पर। लेकिन सवाल उठता है... क्या ये जांच भी... सिर्फ आसान जवाब तलाशने वाली जांच है ?

अब विरोध आया — ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन की ओर से। जोनल महासचिव वी.के. तिवारी ने रेलवे को चिट्ठी लिखी। कहा गया — 'रिपोर्ट में सिग्नल नंबर ही गलत लिखा गया है।' 'बिना फैक्ट-फाईंडिंग जांच के रिपोर्ट जारी करना गलत है।' और 'बिना जांच के रनिंग स्टाफ को दोष देना... उनकी छवि को धूमिल करता है।' यानी, रेलवे की रिपोर्ट पर आधिकारिक आपत्ति दर्ज की गई है।

जवाब में रेल संरक्षा आयुक्त — बी.के. मिश्रा। उन्होंने पदाधिकारियों से मुलाकात की। करीब 40 मिनट तक चली वन-टू-वन चर्चा।

मिश्रा ने पूछा — दुर्घटना पर कुछ कहना है ? उन्होंने कहा — घटना नहीं... लेकिन सेफ्टी से जुड़ी कई बड़ी समस्याएँ हैं।

CRS ने तुरंत कहा — ठीक है, दस्तावेज लेकर दोबारा आइए। यानि जांच अब सिर्फ हादसे की नहीं, बल्कि सिस्टम की सुरक्षा पर भी जा सकती है।

इधर, डीआरएम खोईवाल ने मेमू का ब्रेक ट्रायल करवाया। उसी ट्रैक पर, उसी स्पीड में, उसी हालात में।

डेटा क्या कहता है ? मेमू स्टेशन से निकली — 45 की स्पीड पर। सिग्नल पार किया — 76 किमी प्रति घंटा। और जब इमरजेंसी ब्रेक लगा — स्पीड गिरकर 53 रह गई। यानि ब्रेक ने काम किया।

पर सवाल ये है — क्या सिग्नल ने वक्त पर चेताया था ? क्या कम्युनिकेशन चैनल सही थे ? या फिर सिस्टम... कहीं पीछे रह गया ?

CRS ने इस दौरान लोको पायलट विद्यासागर और असिस्टेंट लोको पायलट रश्मि राज दोनों के प्रशिक्षकों — CLI से भी सवाल किए। 'काउंसलिंग आखिरी बार कब हुई थी ?' हर महीने कितनी बार होती है ?किस तरीके से की जाती है ?

क्योंकि हर बार ह्यूमन एरर कहना आसान है, पर कभी ये नहीं पूछा जाता कि उस इंसान पर सिस्टम का कितना दबाव था।

AILRSA का आरोप साफ है — हर रिपोर्ट में सिस्टम बच जाता है... और स्टाफ फँस जाता है।

कभी सिग्नल क्लियर नहीं होता, कभी इंटरलॉकिंग फेल होती है, कभी कम्युनिकेशन टूट जाता है। लेकिन रिपोर्ट का निष्कर्ष वही — लोको पायलट दोषी। क्या यही है रेलवे की जांच संस्कृति ?

AILRSA ने कहा — फैक्ट फाइंडिंग जांच के बाद ही निष्कर्ष जारी किए जाएँ।

यानि मांग है पारदर्शिता की। एक ऐसी जांच — जो सिर्फ नाम के लिए नहीं, बल्कि हर डेटा, हर सिग्नल, हर सेकंड का विश्लेषण करे। जाँच में मौजूद रेलकर्मियों ने बताया- सिग्नल की विज़िबिलिटी कम थी। ब्रेकिंग डिस्टेंस पर्याप्त नहीं थी।

यानि,तकनीकी चूक के संकेत साफ दिख रहे हैं। पर सवाल वही-क्या ये बातें रिपोर्ट में जगह पाएँगी ? या फिर फिर से सारा दोष एक इंसान पर डाल दिया जाएगा ?

अब CRS ने दस्तावेजी सबूतों की मांग की है। यानि जांच अब सिर्फ 'ओवरशूट' तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे सिगनलिंग सिस्टम, ब्रेकिंग पैटर्न, और सेफ्टी प्रोटोकॉल पर जाएगी। शायद यही कदम... सच्चाई के ज्यादा करीब ले जाए।

रेलवे की पटरी पर दौड़ती हर ट्रेन में सिर्फ इंजन नहीं चलता, चलता है एक भरोसा। लोको पायलट का भरोसा- कि सिग्नल ठीक होगा। ब्रेक काम करेंगे। और सिस्टम उसके साथ है। लेकिन जब हर बार हादसे के बाद सिर्फ उसी इंसान को दोषी ठहरा दिया जाता है, तो सवाल उठता है —'क्यों हर रिपोर्ट में सिस्टम बच जाता है... और स्टाफ फँस जाता है ?'

क्या हमारी जांच भी ऑटो-पायलट मोड पर चल रही है ? मित्रो हादसे रोकने के लिए सिर्फ रिपोर्ट नहीं, सिस्टम की आत्मपरीक्षा जरूरी है।

वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान, सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध - छत्तीसगढ़ का आदर्श मॉडल

बुजुर्ग - संस्कृति, अनुभव और मूल्यों के स्तंभ

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने यह सिद्ध किया है कि संवेदनशील शासन, सुचारु क्रियान्वयन और मानवीय दृष्टिकोण मिलकर बुजुर्गों के जीवन में वास्तविक परिवर्तन ला सकते हैं।

भारतीय संस्कृति के केंद्र में हमारे बुजुर्ग हैं - जिनके अनुभव समाज को दिशा देते हैं और जिनकी स्मृतियाँ हमारी सभ्यता की नींव हैं, लेकिन बदलते सामाजिक परिदृश्य में पारिवारिक संरचना और सामाजिक दायरे सिमटने लगे हैं। ऐसे में वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सहभागिता और गरिमामय जीवन सुनिश्चित करना शासन की प्राथमिकता बन जाता है। इसी भावना को साकार करती है - छत्तीसगढ़ सरकार की संवेदनशील नीतियाँ और सशक्त क्रियान्वयन।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने वरिष्ठजनों के सम्मान को शासन प्रणाली में प्रमुख स्थान दिया है। उनका मानना है 'माता-पिता की पूजा ही ईश्वर की पूजा है।' इसी सोच के साथ राज्य में ऐसे प्रकल्पों का विस्तार हो रहा है जो बुजुर्गों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाते हैं। एक अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने रायपुर, बिलासपुर, कोरबा और दुर्ग में पीपीपी मॉडल के तहत आधुनिक वृद्धाश्रम स्थापित करने तथा असहाय बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के लिए रायपुर में उपकरण सर्विस सेंटर खोलने की घोषणा की। इसी के साथ राज्य में 'सियान गुड़ी' जैसे सामाजिक-आध्यात्मिक केंद्रों का विस्तार बुजुर्गों को मानसिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक सहारा प्रदान कर रहा है।

छत्तीसगढ़ की समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने वृद्धजन केंद्रित कार्यक्रमों को जमीनी स्तर तक पहुँचाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उनका कहना है 'संवेदनशील शासन का अर्थ है, हर बुजुर्ग तक सेवा और सुरक्षा पहुँचाना।'

राज्य में 35 वृद्धाश्रम सक्रिय रूप से संचालित हैं, जहाँ लगभग 1049 वरिष्ठ नागरिक भोजन, आवास, स्वास्थ्य, परामर्श और मनोरंजन की सुविधाएँ प्राप्त कर रहे हैं। गंभीर रोगों या असहाय स्थिति में रह रहे बुजुर्गों के लिए रायपुर, दुर्ग, कबीरधाम, रायगढ़, बालोद और बेमेतरा इन 6 जिलों में प्रशामक देखभाल गृह संचालित किए जा रहे हैं, जहाँ 128 वरिष्ठजनों को निःशुल्क उपचार, दवाइयाँ और नियमित स्वास्थ्य देखभाल मिल रहा है। वरिष्ठजनों की समस्याओं के निवारण हेतु स्थापित हेल्पलाइन सेवा द्वारा अब तक 2 लाख 70 हजार से अधिक प्रकरणों का समाधान किया जा चुका है। यह सेवा न केवल उनकी पहुँच बढ़ाती है, बल्कि आत्मविश्वास और सुरक्षा बोध भी जगाती है।

वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम - 2007 का राज्य में सख्ती से पालन किया जा रहा है। अनुविभाग स्तर पर - भरण-पोषण अधिकरण, जिला स्तर पर - अपीलीय अधिकरण इन व्यवस्थाओं ने बुजुर्गों को संपत्ति, सुरक्षा और भरण-पोषण से जुड़े मामलों में त्वरित न्याय दिलाने का मार्ग प्रशस्त किया है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को नियमित पेंशन सहायता प्रदान की जा रही है 60 से 79 वर्ष तक की आयु के बुजुर्गों को 500 रुपए प्रति माह और 80 वर्ष से अधिक आयु वाले वरिष्ठजनों को 650 रुपए प्रति माह सहायता राशि दी जा रही है। वर्तमान में 14 लाख से अधिक बुजुर्ग इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। यह सहायता उनके जीवन में आर्थिक सुरक्षा का आधार बनती है।

राज्य सरकार की योजनाएँ गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा के अधिकार को सुदृढ़ कर रही हैं। आयुष्मान भारत और शहीद वीर नारायण सिंह स्वास्थ्य सहायता योजनाओं के तहत 8 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क उपचार मिला है। साथ ही वरिष्ठ नागरिक सहायक उपकरण प्रदाय योजना के अंतर्गत 50 हजार से अधिक बुजुर्गों को व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र, छड़ी, चश्मा जैसे उपकरण प्रदान किए गए हैं।

आध्यात्मिक संतोष बुजुर्गों के मानसिक स्वास्थ्य का आधार है। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना और श्री रामलला दर्शन योजना के माध्यम से 2.5 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिक, 278 व्यक्ति तीर्थयात्राओं का लाभ ले चुके हैं। यात्रा के दौरान भोजन, आवास और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। प्रत्येक वर्ष एक अक्टूबर वृद्धजन दिवस राज्य और जिला स्तर पर मनाया जाता है। इन कार्यक्रमों से समाज में बुजुर्गों के प्रति सम्मान, संवेदना और सहयोग की भावना को प्रोत्साहन मिलता है। वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान केवल एक सामाजिक मूल्य नहीं, बल्कि एक कर्तव्य है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने यह सिद्ध किया है कि संवेदनशील शासन, सुचारु क्रियान्वयन और मानवीय दृष्टिकोण मिलकर बुजुर्गों के जीवन में वास्तविक परिवर्तन ला सकते हैं।

छत्तीसगढ़ विधानसभा का 25 साल का इंतजार खत्म

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नए विधानसभा भवन को राज्य को किया समर्पित

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन के लोकार्पण के साथ ही विधानसभा के खुद के भवन का 25 साल का इंतजार खत्म हो गया। राज्य निर्माण के रजत जयंती वर्ष में राज्योत्सव के मौके पर छत्तीसगढ़ को अपना भव्य और आधुनिक विधानसभा भवन मिला। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मुख्य आतिथ्य में नए विधानसभा परिसर में आयोजित लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने कहा कि यह हम सबके लिए बहुत गौरव का क्षण है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का सदैव लोकतांत्रिक परंपराओं पर गहरा विश्वास रहा है। राज्य की समृद्धि और खुशहाली के फैसले अब इस भवन में होंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि यहां राज्य के हित से जुड़े विधेयकों व मुद्दों पर सार्थक चर्चा से जनता की आकांक्षाएं और अपेक्षाएं पूर्ण होंगी। यह नया भवन छत्तीसगढ़ विधानसभा की परंपरा तथा लोकतंत्र की भावनाओं को और मजबूत करेगी एवं इसका गौरव बढ़ाएंगी।

रजत जयंती वर्ष में छत्तीसगढ़ को मिला अपना भव्य विधानसभा भवन

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कार्यक्रम में अपने संबोधन में कहा कि आज का दिन भगवान श्रीराम के ननिहाल और माता कौशल्या की धरती छत्तीसगढ़ के लिए स्वर्णिम है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का पिछले 25 वर्षों में गौरवशाली इतिहास रहा है। राज्य सरकार पिछले 21-22 महीनों से मोदी की गारंटी को पूरा करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को अटलजी ने बनाया है और मोदी जी इसे संवारने का काम कर रहे हैं।

छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज प्रदेश के लिए ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण क्षण है। आज यह भवन, भूमि और मंच अभूतपूर्व समय का साक्षी बन रहा है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में आज का दिन स्वर्णिम अक्षरों में अंकित रहेगा। आज के दिन ही 25 वर्ष पहले स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने राज्य का निर्माण किया था और आज ही यह अपने निर्माण से विधान तक का सफर पूरा कर रहा है। उन्होंने बताया कि नया विधानसभा भवन 80 प्रतिशत स्वदेशी मटेरियल से बना है। सदन में बस्तर के सागौन से निर्मित फर्नीचर और दरवाजे हैं, सीलिंग

324 करोड़ की लागत से बना 51 एकड़ में फैला परिसर

कुल 51 एकड़ में फैले इस परिसर का निर्माण 324 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। भवन को तीन मुख्य हिस्सों—विंग-ए, विंग-बी और विंग-सी—में विभाजित किया गया है। विंग-ए में विधानसभा का सचिवालय, विंग-बी में सदन, सेंट्रल हॉल, मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय, तथा विंग-सी में मंत्रियों के कार्यालय स्थित हैं।

हरित तकनीक से निर्मित पर्यावरण अनुकूल भवन

यह भवन पूरी तरह पर्यावरण अनुकूल और हरित निर्माण तकनीक से बनाया गया है। परिसर में सोलर प्लांट की स्थापना के साथ वर्षा जल संचयन हेतु दो सरोवर भी बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा, भवन में पर्यावरण-संरक्षण के सभी मानकों का पालन किया गया है।

500 सीटर ऑडिटोरियम और 200 सीटर सेंट्रल हॉल

विधानसभा भवन में 500 दर्शक क्षमता वाला अत्याधुनिक ऑडिटोरियम और 200 सीटर सेंट्रल हॉल बनाया गया है। भवन की वास्तुकला आधुनिकता और पारंपरिक शैलियों का उत्कृष्ट मेल है।

में धान की बालियों की कलाकारी है। छत्तीसगढ़ को यहां समाहित किया गया है। राज्यपाल श्री रमेन डेका, केन्द्रीय आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्रीद्वय श्री अरुण साव और श्री विजय शर्मा, संसदीय कार्य मंत्री श्री केदार कश्यप, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत और सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल भी विधानसभा भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए।

खूबसूरत इमारत ही नहीं, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, परंपरा और आस्था का प्रतीक

छत्तीसगढ़ के इतिहास में आज 1 नवम्बर के दिन एक नया अध्याय जुड़ा। वर्ष 2000 में राज्य गठन के बाद रायपुर के राजकुमार कॉलेज से शुरू हुई छत्तीसगढ़ विधानसभा को 25 वर्षों के बाद रजत जयंती वर्ष में अपना भव्य, आधुनिक और पूर्ण सुविधायुक्त स्थायी भवन मिल गया है। यह भवन केवल एक खूबसूरत इमारत ही नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की समृद्ध संस्कृति, परंपरा और आस्था का प्रतीक भी है।

कृषि-प्रधान संस्कृति और बस्तर के काष्ठ शिल्प की झलक

'धान का कटोरा' कहलाने वाले छत्तीसगढ़ की पहचान को इस भवन की वास्तुकला में बखूबी पिरोया गया है। विधानसभा के सदन की सीलिंग पर धान की बालियों और पत्तियों को उकेरा गया है, जो प्रदेश की कृषि-प्रधान संस्कृति का प्रतीक है। भवन के ज्यादातर दरवाजे और फर्नीचर बस्तर के पारंपरिक काष्ठ शिल्पियों द्वारा बनाए गए हैं। इस तरह नया विधानसभा भवन आधुनिकता और परंपरा का एक जीवंत संगम बन गया है।

भविष्य की जरूरतों के अनुरूप अत्याधुनिक भवन

नए विधानसभा भवन को वर्तमान और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। यह पूरी तरह सर्वसुविधायुक्त और सुसज्जित भवन है, जिसके सदन को 200 सदस्यों तक के बैठने के लिए विस्तारित किया जा सकता है। पेपरलेस विधानसभा संचालन के लिए आवश्यक तकनीकी सुविधाओं का समावेश भी किया गया है, जिससे यह भवन 'स्मार्ट विधानसभा' के रूप में विकसित होगा।

तीन करोड़ जनता की आकांक्षाओं का प्रतीक

छत्तीसगढ़ की संस्कृति और शिल्प से सजे-संवरे इस नए विधानसभा भवन में राज्य के तीन करोड़ नागरिकों की उम्मीदें, आकांक्षाएं और आत्मगौरव साकार होता दिखेगा। यह भवन न केवल लोकतांत्रिक व्यवस्था का, बल्कि छत्तीसगढ़ की पहचान, प्रगति और परंपरा का प्रतीक भी बनेगा।

परंपरा और आधुनिकता का संगम छत्तीसगढ़ विधानसभा का नया भवन- लोकसभाध्यक्ष

लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने इस समारोह में भाग लिया और छत्तीसगढ़ के लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि विधानमंडल ऐसी संस्थाएं हैं जो विश्वास का साकार रूप हैं और नागरिकों की आस्था एवं आकांक्षाओं का प्रतीक हैं। उन्होंने आगे कहा कि इन संस्थाओं में होने वाली चर्चाओं और विचार-विमर्श की गुणवत्ता ही लोकतंत्र की मजबूती और शासन की सफलता का निर्धारण करती है।

राज्योत्सव पर वायु सेना की टीम का रोमांचक एयर शो

छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ पर नवा रायपुर के सेंध जलाशय के ऊपर भारतीय वायु सेना की प्रतिष्ठित एरोबेटिक 'सूर्यकिरण' की टीम ने रोमांचक एयर शो का प्रदर्शन किया। देश के उप राष्ट्रपति श्री सी.पी. राधाकृष्णन, राज्यपाल श्री रमेन डेका, मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह के साथ हजारों लोगों ने अद्भुत और रोमांचक एयर शो का आनंद लिया। आज प्रदेशवासियों के लिए वायु सेना का एयर शो कमाल का अनुभव रहा। सेंध जलाशय के ऊपर वायु सेना के फाइटर प्लेन्स ने एक के बाद एक कई हवाई करतब दिखाए। आसमान में पंछियों के झुंड की तरह बिल्कुल क्रम से उड़ने वाले फाइटर प्लेन्स के माध्यम से वायु सेना के जाबांजों ने अपने नियंत्रण और शौर्य का अद्भुत प्रदर्शन किया। विमानों के माध्यम से जब आकाश में तिरंगा लहराया तो सेंध जलाशय भारत माता की जय के नारे से गूंज उठा।

एयर शो के दौरान 'सूर्यकिरण' टीम के लीडर ग्रुप कैप्टन श्री अजय दशरथी ने आसमान से छत्तीसगढ़वासियों को रजत महोत्सव की बधाई दी। वहीं छत्तीसगढ़ निवासी भारतीय वायु सेना के स्क्वाड्रन लीडर श्री गौरव पटेल ने सेंध जलाशय के ऊपर अपने कॉकपिट से 'जय जोहार' और 'छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया' कहकर दर्शकों का अभिवादन किया। उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप, खाद्य मंत्री श्री दयाल दास बघेल, स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा, वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब और सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल सहित विभिन्न निगमों, मंडलों और आयोगों के पदाधिकारी भी एयर शो देखने पहुंचे थे।

'सूर्यकिरण' टीम ने अनुशासन, परस्पर विश्वास, सटीकता और उत्साह के साथ एक घंटे तक वायु सेना के विमानों के साथ कलाबाजी दिखाकर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। नवा रायपुर के सेंध जलाशय में मौजूद हजारों दर्शक पायलटों के हैरतअंगेज साहस और करतबों को देखकर मंत्रमुग्ध होते रहे। विंग कमांडर श्री ए.व्ही. सिंह के नेतृत्व में वन-एफ-9 और वन-एफ-8 हेलीकॉप्टर यूनिट ने वी-17 और वी-5 हेलीकॉप्टरों से स्लीपरी और स्काई-ऑपरेशन के करतब दिखाए। 'आदिदेव' नाम के इन हेलीकॉप्टरों से केवल 15 मीटर ऊंचाई पर स्थिर रहकर 14 गरूड़ कमांडोज रस्सी के सहारे नीचे उतरे। वहीं स्काई-ऑपरेशन के दौरान आठ गरूड़ कमांडोज रस्सी पर लटककर हेलीकॉप्टर से दर्शकों के सामने से आकाश में उड़ते हुए गुजरे। इन दोनों ऑपरेशनों को लड़ाई और आपदा के दौरान जनसामान्य को बचाने के लिए किया जाता है।

एयर शो में 'सूर्यकिरण' की टीम के नौ हॉक-मार्क-123 फाइटर विमानों ने आसमान में हार्ट, डायमंड, लूप, ग्रोवर, डान लाइट, कॉम्बैट तेजस जैसे शानदार फार्मेशन बनाकर लोगों को रोमांचित किया। नीले आसमान में उड़ते लाल-सफेद जेट विमानों द्वारा तिरंगे की आकर्षक ट्रेल छोड़ने पर सेंध जलाशय परिसर तालियों और जय-हिंद के नारों से गूंज उठा। हजारों की संख्या में मौजूद नागरिक, युवा और बच्चे लगातार विमानों की कलाबाजियों को अपने कैमरों और मोबाइलों में कैद करते रहे।

वायु सेना के जाबांज फाइटर पायलटों ने आसमान में दिल की आकृति बनाकर 25वें राज्योत्सव की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने तिरंगे के तीन रंगों से डीएनए की आकृति बनाकर तिरंगे के प्रति अपना सम्मान प्रस्तुत किया। उन्होंने 360ए में फाइटर जेट उड़ाते हुए उल्टा जेट भी उड़ाया। तेजस और युवाओं को समर्पित अंग्रेजी अक्षर 'वाई' की आकृति बनाने के साथ ही कई करतब दिखाए। टीम का प्रदर्शन केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि युवाओं में देशप्रेम, साहस और भारतीय सशस्त्र बलों में सेवा की प्रेरणा जगाने का संदेश भी देता है।

फ्लाइट लेफ्टिनेंट सुश्री कंवल संधू ने अपनी लाइव कमेंट्री के दौरान एयर शो के रोमांचक वर्णन के साथ ही पायलटों के अनुशासन, समर्पण, प्रशिक्षण और जोखिम प्रबंधन की बारीकियों की जानकारी दी।

'सूर्यकिरण' एशिया की एकमात्र नौ लड़ाकू विमानों वाली एरोबैटिक टीम, 1996 में हुई थी स्थापना

भारतीय वायु सेना की सूर्यकिरण एरोबैटिक टीम एशिया की एकमात्र नौ लड़ाकू विमानों वाली एरोबैटिक टीम है। यह विशिष्ट टीम भारत में ही निर्मित एचएएल (HAL) लाइसेंस प्राप्त हॉक एमके-132 (Mk-132) विमान उड़ाती है। इन विमानों के जरिए भारतीय वायु सेना की सटीकता, पेशेवर उत्कृष्टता और कौशल का अद्भुत प्रदर्शन करती है, जिसमें रोमांचक हवाई करतब और बेहद सटीक फॉर्मेशन शामिल होते हैं। सूर्यकिरण टीम को उसका मिशन विशेष बनाता है। देश के युवाओं को भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल होकर देशसेवा के लिए प्रेरित करना इनका मिशन है।

राज्य सरकार के प्रयासों से श्रमिकों के जीवन में आ रहा है बदलाव

श्रम विभाग अंतर्गत 25 वर्षों की विभागीय उपलब्धियां

> **ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत विभिन्न श्रम कानूनों के अंतर्गत कारखानों, दुकान व स्थापनाओं, ठेकेदारों आदि का पंजीयन, नवीनीकरण, संशोधन तथा विभाग अंतर्गत गठित मंडलों में श्रमिकों के पंजीयन, नवीनीकरण, संशोधन तथा योजनाओं हेतु आवेदन/स्वीकृति विभागीय वेब पोर्टल एवं श्रमेव जयते मोबाईल एप के माध्यम से ऑनलाईन की जा रही है।**

छगन लोन्हारे

छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के समय 16 जिलों में से 09 जिलों में श्रम कार्यालय तथा 04 जिलों में औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यालय संचालित है। वर्तमान में राज्य के समस्त 33 जिलों में श्रम कार्यालय तथा 10 जिलों में औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा तथा वर्ष 2008 से रायपुर में इंडस्ट्रीयल हाईजिन लैब का राज्य स्तरीय कार्यालय प्रारंभ किया गया है। राज्य स्थापना के बाद से वर्ष 2008 में छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल तथा वर्ष 2011 में छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल का गठन किया गया है। उक्त मण्डलों में श्रमिकों के पंजीयन, नवीनीकरण तथा विभिन्न योजनाओं में आवेदन विभागीय पोर्टल/श्रमेव जयते मोबाईल ऐप के माध्यम से ऑनलाईन करने की सुविधा दी गयी है तथा विभिन्न योजनाओं में डी0बी0टी0 के माध्यम से श्रमिकों को लाभान्वित किया जा रहा है।

52 लाख 75 हजार 618

संगठित/निर्माण/असंगठित श्रमिक पंजीकृत

31 जुलाई, 2025 तक छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल अंतर्गत 5लाख 41 हजार 920 संगठित श्रमिक, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल अंतर्गत 30 लाख 21 हजार 624 निर्माण श्रमिक तथा छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल अंतर्गत 17 लाख 12 हजार 074 असंगठित श्रमिक पंजीकृत हैं। इस प्रकार विभाग अंतर्गत संचालित मंडलों में कुल 52 लाख 75 हजार 618 संगठित, निर्माण, असंगठित श्रमिक पंजीकृत हैं। राज्य स्थापना के बाद से 57 लाख 24 हजार 745 श्रमिकों को 23 अरब 70 करोड़ 24 लाख 56 हजार 757 रूपये से लाभांवित किया गया।

छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल में 80 लाख 713 संगठित श्रमिक को 31 जुलाई, 2025 तक राशि रूपये 26 करोड़ 56 लाख 2 हजार 131 से, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल में 51 लाख 72, हजार 579 निर्माण श्रमिकों को राशि रूपये 19 करोड़ 82 लाख 69 लाख 48 हजार 448 तथा छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल में 4 लाख 71 हजार 453 असंगठित कर्मकारों को राशि रूपये 3अरब 60 करोड़ 99 लाख 06 हजार 178 से इस प्रकार राज्य स्थापना के बाद से कुल 57 लाख 24 हजार 745 श्रमिकों को राशि रूपये 23 अरब 70 करोड़ 24 लाख 56 हजार 757 (तेईस अरब सत्तर करोड़ चौबीस लाख छप्पन हजार सात सौ सात रूपये) से लाभांवित किया गया है।

श्रमिक सहायता केन्द्र 24×7 संचालित

श्रमिकों के हितलाभ संरक्षण, सहायता एवं उनके शिकायतों के निराकरण करने के लिए राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता केन्द्र (Helpline Center) रायपुर में 24×7 संचालित है। प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय तथा समस्त विकासखंडों में मुख्यमंत्री श्रम संसाधन केन्द्र संचालित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से 31 जुलाई 2025 तक 84 हजार 810 निर्माण श्रमिकों को पंजीयन एवं योजनाओं के आवेदन में सहयोग प्रदान किया गया है।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत विभिन्न श्रम कानूनों के अंतर्गत कारखानों, दुकान व स्थापनाओं, ठेकेदारों आदि का पंजीयन, नवीनीकरण, संशोधन तथा विभाग अंतर्गत गठित

मंडलों में श्रमिकों के पंजीयन, नवीनीकरण, संशोधन तथा योजनाओं हेतु आवेदन/स्वीकृति विभागीय वेब पोर्टल एवं श्रमेव जयते मोबाईल एप के माध्यम से ऑनलाईन की जा रही है। साथ ही विभिन्न श्रम अधिनियमों के अंतर्गत पंजियों/अभिलेखों को ऑनलाईन डिजिटल रूप में संधारित करने तथा एकीकृत वार्षिक विवरणी ऑनलाईन प्रस्तुत करने की सुविधा नियोजकों को प्रदान की गई है।

ई-गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार

भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा छ0ग0 शासन श्रम विभाग को 2020-21 हेतु 'ई-श्रमिक सेवा' सहित सार्वभौमिक पहुंच हेतु 'ई-गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार' रूपये 02 लाख पुरस्कार राशि के साथ गोल्ड पुरस्कार प्रदान किया गया।

प्रवासी श्रमिकों के हित संरक्षण, कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विभागों के समन्वय से दिनांक 19 जुलाई 2021 से छ0ग0 राज्य प्रवासी श्रमिक नीति, 2020 लागू किया गया है, जिसमें पलायन पंजी के ऑनलाईन संधारण की व्यवस्था की गई है।

श्रमिक परिवारों के बच्चों के लिये अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना

मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा एवं श्रम मंत्री के निर्देशानुसार पंजीकृत निर्माण श्रमिक परिवारों के बच्चों को उत्कृष्ट निजी शालाओं में निःशुल्क अध्ययन कराये जाने हेतु छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा 'अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना' 08.जनवरी 2025 से प्रारंभ की गई है। योजना के तहत मंडल में 01 वर्ष पूर्व पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के प्रथम 02 बच्चों को कक्षा 6 वीं में प्रवेश दिया जाकर कक्षा 12 वीं तक आवासीय विद्यालयों में वर्तमान में 100 श्रमिकों के बच्चों को विभिन्न विद्यालयों में प्रवेश दिया जाकर गुणवत्तायुक्त निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जा रहा है। निर्माण श्रमिकों के स्वयं के आवास क्रय एवं आवास निर्माण हेतु एक लाख रूपये एकमुश्त अनुदान सहायता राशि प्रदाय किया जा रहा है। 31 जुलाई 2025 तक 2 हजार 278 निर्माण श्रमिकों को नवीन आवास क्रय/आवास निर्माण हेतु अनुदान सहायता राशि प्रदाय किया जा चुका है।

निर्माण श्रमिकों के लिये पेंशन योजना

60 वर्ष आयु पूर्ण कर चुके पंजीकृत निर्माण श्रमिक, जिनका मंडल में 10 वर्ष पूर्व का पंजीयन हो, ऐसे 37 निर्माण श्रमिकों को प्रतिमाह रूपये 1500/- पेंशन योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना इस योजना अंतर्गत पंजीकृत निर्माण, असंगठित एवं संगठित श्रमिकों को रूपये 05 में गरम एवं पौष्टिक भोजन प्रदाय किया जा रहा है। प्रदेश के 17 जिलों में 37 श्रम अन्न योजना केन्द्र संचालित है, जिसमें प्रतिदिन लगभग 8 हजार श्रमिक गरम भोजन प्राप्त कर रहें है।

संचालनालय, कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा योजना, राज्य निर्माण के समय श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदाय करने वाली यह योजना केवल कारखानों, सिनेमाघरों, ट्रांसपोर्ट, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर लागू थी। राज्य निर्माण के पश्चात इस योजना में निजी सहायता प्राप्त शैक्षणिक एवं निजि चिकित्सा संस्थाओं तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित नगर निगमों, नगर पालिकाएं, नगर परिषद् एवं अन्य स्थानीय निकाय पर भी लागू की गई है।

निःशुल्क चिकित्सा हित लाभ

छ.ग. राज्य गठन के उपरांत कर्मचारी राज्य बीमा योजना का विस्तार छ.ग. राज्य के 15 जिलों के सम्पूर्ण क्षेत्र तथा 17 जिलों के नगरीय निकाय क्षेत्रों में किया गया है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत छ.ग. राज्य निर्माण के पूर्व लगभग 30 हजार कामगार बीमित होकर राज्य के संचालनालय, कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें के अंतर्गत संचालित औषधालयों के माध्यम से निःशुल्क चिकित्सा हितलाभ प्राप्त कर रहे थे, जो कि अब बढ़कर लगभग 6 लाख 25 हजार हो गये हैं।

राज्य निर्माण के पूर्व छ.ग. राज्य में केवल 6 औषधालय संचालित थी जो अब बढ़कर 42 हो गई है। बीमित हितग्राहियों को बेहतर चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये राज्य के रायपुर, कोरबा, भिलाई तथा रायगढ़ में एक-एक 100 बिस्तरयुक्त चिकित्सालय का निर्माण कर्मचारी राज्य बीमा निगम के द्वारा किया गया है।

बीमित हितग्राहियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधायें

राज्य निर्माण के पूर्व बीमित हितग्राहियों को अंतःरोगी उपचार पर होने वाले व्यय का वहन पहले स्वयं करना पड़ता था फिर वे चिकित्सा पुनर्भुगतान हेतु अपना देयक प्रस्तुत करते थे। राज्य निर्माण के पश्चात् वर्ष 2014 में बीमित हितग्राहियों को कैशलेस आधार पर सेकेण्डरी केयर चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये निजी चिकित्सालयों को अधिकृत किया गया है। अधिकृत किये गये चिकित्सालयों में बीमित हितग्राहियों को कैशलेस आधार पर सेकेण्डरी केयर चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही है।

बीमित हितग्राहियों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा उनके प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ कर्मचारी राज्य बीमा सोसायटी का गठन वर्ष 2018 में किया गया है, जिसका लाभ पंजीकृत श्रमिक उठा रहे हैं।

नई उड़ान, नया क्षितिज

छत्तीसगढ़ में महतारियों के सशक्तिकरण की कहानी

छत्तीसगढ़ अपने विकास-यात्रा के स्वर्णिम पड़ाव पर है। इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण आधार बनी है – राज्य की महिलाएँ, जिन्हें स्नेह व सम्मान से 'महतारी' कहा जाता है। बीते वर्षों में छत्तीसगढ़ सरकार ने महिला सशक्तिकरण को केवल नीतिगत प्राथमिकता नहीं बनाया, बल्कि सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की धुरी के रूप में स्थापित किया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में आज महिलाएँ योजनाओं की लाभार्थी मात्र नहीं, परिवर्तन की वाहक बनकर उभरी हैं। राज्य में महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए सरकार ने विविध योजनाएँ शुरू की हैं। सबसे उल्लेखनीय महतारी वंदन योजना है, जिसके तहत लगभग 70 लाख महिलाओं को अब तक 12,983 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई है। यह सहायता महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा ही नहीं, बल्कि परिवार व समाज में निर्णायक भूमिका निभाने की क्षमता भी प्रदान करती है।

दीदी ई-रिक्शा योजना ने 12,000 महिलाओं को रोजगार के नए अवसर दिए। सक्षम योजना के तहत 32,000 महिलाओं को 3 प्रतिशत ब्याज पर 2 लाख रुपए तक व्यवसायिक ऋण दिया गया, जबकि महतारी शक्ति ऋण ने 50,000 महिलाओं को बिना जमानत ऋण प्रदान कर आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त किया। मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना से 1.15 लाख महिलाएँ घर-परिवार के साथ उत्पादन कार्य से जुड़कर सम्मानजनक आय अर्जित कर रही हैं।

कोंडागांव की रत्तो बाई का जीवन कभी नक्सली भय से घिरा था। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) से उन्हें 1.20 रुपए लाख और मनरेगा से 90 दिन का रोजगार मिला। आज वे पक्के घर में सुरक्षित जीवन जीती हैं और सब्जी विक्रय के माध्यम से जीवन यापन करती हैं। उज्ज्वला, नल-जल जैसी सुविधाएँ उनके जीवन में प्रकाश भर रही हैं। दंतेवाड़ा जिले की गंगादेवी SHG की महिलाएँ आज टाटा मैजिक वाहन का संचालन कर 26,000 रुपए मासिक आय अर्जित कर रही हैं। यह उदाहरण बताता है कि ग्रामीण महिलाएँ अवसर मिलने पर कैसे नए व्यवसायों का संचालन कर सकती हैं।

सरगुजा की श्रीमती श्यामा सिंह ने बिहान योजना के तहत 95,000 रुपए की सहायता से 30 सेंट्रिंग प्लेट से काम शुरू किया। आज उनके पास 152 प्लेट हैं तथा वे 50,000 रुपए प्रतिमाह कमाती हैं। कोरबा की श्रीमती मंजलीन बाई की छब्बा फंड से स्वास्थ्य केंद्र में नियुक्त होकर उन्हें 9,000 रुपए मासिक मानदेय मिलता है। यह न सिर्फ आर्थिक स्थिरता, बल्कि सामाजिक सम्मान भी देता है।

कभी नक्सली हिंसा से भयभीत बस्तर आज नए परिदृश्य के साथ उभर रहा है। यह इलाका आत्मनिर्भरता, सम्मान और अवसरों की नई पहचान बन गया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय कहते हैं कि 'बस्तर का पुनर्निर्माण केवल सड़क या पुल बनाना नहीं, यह वहाँ के हर घर में विश्वास का दीप जलाने का संकल्प है।' केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 15,000 विशेष आवास स्वीकृत किए, जिनमें से 3,000 बस्तर, सुकमा, कांकेर, बीजापुर और दंतेवाड़ा में बन रहे हैं। अब तक 12,000 से अधिक लोग सुरक्षित आवास पा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में महिला SHG की संख्या 2,80,362 है, जिनमें से लगभग 60,000 समूह बस्तर में सक्रिय हैं। वनोपज और हस्तशिल्प आधारित उद्यमों से करोड़ों का कारोबार हो रहा है। 'लखपति महिला मिशन' के अंतर्गत 2,000 महिलाएँ सालाना 1 लाख रुपए से अधिक कमाती हैं। 'जशप्योर' और बस्तर बैंत उत्पाद राष्ट्रीय पहचान पा चुके हैं। महिलाएँ अब रोजगार पाने तक सीमित नहीं, बल्कि रोजगार-दाता भी बन रही हैं।

स्वास्थ्य और सुविधा को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की उज्ज्वला योजना के अंतर्गत स्वीकृत 25 लाख नए LPG कनेक्शन में से 1.59 लाख कनेक्शन छत्तीसगढ़ को मिले, जिससे नियद नेल्लानार ग्रामों की महिलाएं भी लाभान्वित हो रही हैं। मुख्यमंत्री श्री साय कहते हैं -'स्वच्छ रसोई, स्वस्थ परिवार और सशक्त महिला' – यही उज्ज्वला का सार है।

छत्तीसगढ़ के 27 जिलों में सखी वन-स्टॉप सेंटर स्थापित हैं, महिला हेल्पलाइन - 181, डायल - 112, 24/7 कार्यरत हैं। नवाबिहान योजना से कानूनी व परामर्श सहायता दी जा रही है। शुचिता योजना से 3 लाख किशोरियाँ लाभान्वित हो रही हैं। 2,000 स्कूलों में नैपकिन वेंडिंग मशीन लगाई गई है। इन पहलों ने महिलाओं के मन में सुरक्षा और आत्मविश्वास की नई ऊर्जा भरी है।

योजनाएँ महिलाओं को तकनीक-आधारित सशक्तिकरण की ओर ले जा रही हैं। ड्रोन दीदी योजना से महिलाओं का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जशप्योर ब्रांड से लगभग 500 महिलाएँ, 10,000 रुपए प्रति माह कमा रही हैं। नवा रायपुर के यूनिटी मॉल में SHG उत्पादों को प्राथमिकता दी जा रही है। ये नारी शक्ति को स्थानीय से राष्ट्रीय बाजार तक पहुँचाने का मार्ग तैयार कर रही हैं।

महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े कहती हैं कि नया छत्तीसगढ़ वह होगा जहाँ भय नहीं, विश्वास होगा, जहाँ महिलाएँ आश्रित नहीं, सशक्त होंगी। आज छत्तीसगढ़ का हर गाँव, हर घर, हर परिवार में बदलाव की अग्नि प्रज्वलित है। जहाँ पहले भय था – वहाँ आज आत्मनिर्भरता है। जहाँ मजबूरी थी- वहाँ आज सम्मान है। छत्तीसगढ़ की महतारियाँ अब परिवर्तन की राह नहीं देख रहीं- वे स्वयं परिवर्तन की दिशा रच रही हैं।

लखपति दीदी महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण समृद्धि की मिसाल

राजनांदगांव में लखपति दीदी सम्मेलन में शामिल हुए उपराष्ट्रपति राज्यपाल और मुख्यमंत्री

राजनांदगांव के स्टेट हाई स्कूल मैदान में आयोजित लखपति दीदी सम्मेलन में देश के उपराष्ट्रपति श्री सी.पी. राधाकृष्णन, राज्यपाल श्री रमेन डेका, मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह सहित अनेक जनप्रतिनिधि शामिल हुए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने महतारी वंदन योजना और नियद नेल्लानार योजना के तहत 69 लाख 15 हजार 273 हितग्राहियों को कुल 647 करोड़ 28 लाख 36 हजार 500 रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से अंतरित की।

इस अवसर पर उपराष्ट्रपति श्री राधाकृष्णन ने कहा कि लखपति दीदी आत्मनिर्भरता और सम्मान का प्रतीक हैं। यह केवल आय का कार्यक्रम नहीं, बल्कि महिलाओं के आत्मविश्वास और समाज में उनके बढ़ते प्रभाव का उत्सव है। उन्होंने कहा कि राजनांदगांव जिला महिला सशक्तिकरण का उदाहरण बन चुका है, जहां महिलाएं आर्थिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर अग्रसर हैं।

उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए चल रहे प्रयासों की सराहना की और कहा कि छत्तीसगढ़ आज बिजली उत्पादन, स्वास्थ्य, शिक्षा और अधोसंरचना के क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि लखपति दीदी आंदोलन दिखाता है कि जब महिलाएं संगठित होती हैं, तो परिवर्तन की गाथाएं स्वयं लिखती हैं।

अपने संबोधन में राज्यपाल श्री रमेन डेका ने कहा कि लखपति दीदी सम्मेलन केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि यह आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ की जीवंत तस्वीर है। यह सम्मेलन इस बात का प्रमाण है कि ग्रामीण महिलाओं की मेहनत, संकल्प और आत्मबल से कैसे समृद्धि का नया अध्याय लिखा जा सकता है।

उन्होंने कहा कि आज हर जिले में महिलाएं स्वसहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक रूप से सक्षम हो रही हैं। बलरामपुर में महिलाएं बाड़ी विकास और विपणन में, बस्तर में वनोपज से जैविक उत्पाद तैयार करने में, और कोण्डागांव में फूड प्रोसेसिंग, सिलाई-कढ़ाई जैसे कार्यों में उल्लेखनीय योगदान दे रही हैं।

राजनांदगांव जिले में ही लगभग 40 हजार लखपति दीदियां बनी हैं, जिनमें से 208 दीदियां सालाना 5 लाख रुपए से अधिक और 26 दीदियां 10 लाख रुपए से अधिक का व्यवसाय कर रही हैं। उन्होंने कहा कि यह आंकड़ा केवल आर्थिक उपलब्धि नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि हर दीदी की कहानी प्रेरणा है। जब संकल्प और सामूहिक प्रयास जुड़ते हैं, तो आत्मनिर्भरता केवल सपना नहीं रहती, वह हकीकत बन जाती है।

राज्यपाल ने पद्मश्री फूलबासन बाई यादव जैसी महिलाओं के कार्यों को आदर्श बताते हुए कहा कि उनके प्रयासों से नारी सशक्तिकरण का मार्ग और सशक्त हुआ है।

राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में महिला उद्यमिता और स्वरोजगार के लिए देशभर में अनेक योजनाएं चल रही हैं, और

छत्तीसगढ़ ने उन्हें जमीन पर उतारकर एक 'सशक्त भारत, सशक्त छत्तीसगढ़' की मिसाल पेश की है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश में 7 लाख 82 हजार लखपति दीदी बनाने का है, जिनमें से अब तक 4 लाख 93 हजार दीदियां आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना से 70 लाख महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपए की सहायता दी जा रही है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि नियद नेल्लानार योजना से बस्तर के दूरस्थ इलाकों में बिजली, पानी और सड़क जैसी सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनेगा।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि लखपति दीदी सम्मेलन नारी शक्ति की पहचान और आत्मनिर्भरता की मिसाल है। उन्होंने कहा कि राजनांदगांव जिले ने विकास की दिशा में नई ऊंचाइयां हासिल की हैं चाहे वह पीएम आवास निर्माण हो, जल संरक्षण या कुपोषण उन्मूलन का अभियान।

उन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाने और आत्मनिर्भरता के लिए प्रेरित करने हेतु पद्मश्री फूलबासन बाई यादव के योगदान की भी प्रशंसा की। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेन्द्र यादव, श्रम कल्याण मंडल अध्यक्ष योगेशदत्त मिश्रा, पूर्व सांसद प्रदीप गांधी, सहित अन्य जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में महिला स्वसहायता समूह की दीदियां उपस्थित थीं।

उपराष्ट्रपति छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव के समापन समारोह में शामिल हुए

उपराष्ट्रपति श्री सी. पी. राधाकृष्णन आज नवा रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। यह आयोजन छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया, जिसमें राज्य की विकास, प्रगति और सांस्कृतिक समृद्धि की प्रेरक यात्रा का जश्न मनाया गया।

उपराष्ट्रपति ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए, इस ऐतिहासिक रजत जयंती समारोह में छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ शामिल होने पर अपार प्रसन्नता व्यक्त की जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किया था। इस पाँच दिवसीय महोत्सव में लोगों ने छत्तीसगढ़ की समृद्ध संस्कृति और इसके प्रभावशाली सामाजिक-आर्थिक बदलाव की झलक देखी।

उपराष्ट्रपति ने 1 नवम्बर 2000 को राज्य के निर्माण में स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के दूरदर्शी नेतृत्व को गर्व से याद किया और एक पूर्व लोकसभा सांसद के रूप में अपने जुड़ाव को व्यक्तिगत तौर पर प्रकट किया, जब उन्होंने राज्य पुनर्गठन विधेयक का समर्थन किया था। उन्होंने छत्तीसगढ़ की असाधारण 25 साल की यात्रा की सराहना की - भारत के सबसे युवा राज्यों में से एक होने से लेकर सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में प्रगति के एक मॉडल के रूप में उभरने तक।

श्री सी.पी. राधाकृष्णन ने नक्सलवाद के खतरे को खत्म करने में राज्य की सफलता की सराहना की और इसका श्रेय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के दृढ़ नेतृत्व के साथ-साथ राज्य सरकार, सुरक्षा बलों और स्थानीय समुदायों के समर्पित प्रयासों को दिया। उन्होंने कहा कि विकास और विश्वास ने छत्तीसगढ़ में भय और हिंसा का स्थान ले लिया है।

उपराष्ट्रपति ने छत्तीसगढ़ की सफलता की नींव रखने वाले लोगों - किसानों, जनजातीय समुदायों, उद्यमियों, शिक्षकों और युवाओं - की सराहना की। उन्होंने राज्य की अनुकरणीय सार्वजनिक वितरण प्रणाली की विशेष रूप से सराहना की, जो 72 लाख से अधिक लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान करती है, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह को बधाई दी। श्री सी.पी. राधाकृष्णन ने राज्य की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए आदिवासी समुदायों को सम्मान दिया। उन्होंने आदिवासी समुदायों की बुद्धिमत्ता, संस्कृति और सतत जीवन शैली की सराहना की, जो आज के पारिस्थितिक और सामाजिक संदर्भ में गहरी प्रासंगिकता रखती है।

उपराष्ट्रपति ने राज्य में उल्लेखनीय बुनियादी ढांचे के विकास पर भी प्रकाश डाला, जिसमें व्यापक सड़क, रेल, एक्सप्रेसवे और हवाई अड्डे की कनेक्टिविटी शामिल है, जिसने सुदूरवर्ती जिलों को राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ा है। उन्होंने नवा रायपुर की भारत के पहले ग्रीनफील्ड शहर के रूप में प्रशंसा की, जो आईटी हब, फार्मा हब, एआई डेटा सेंटर पार्क और उन्नत स्वास्थ्य सेवा के लिए एक विश्वस्तरीय मेडिसिटी जैसी नई-पुरानी पहलों के माध्यम से एक वैश्विक क्षमता केन्द्र बनने के लिए तैयार है।

सशक्त लोकतंत्र के लिए आवश्यक कदम- मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण

लोकतंत्र की जड़ें तभी सशक्त और स्थायी बन सकती हैं, जब प्रत्येक पात्र भारतीय नागरिक को मतदान का अधिकार सुनिश्चित हो। इसी मूल भावना को साकार करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) की प्रक्रिया प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। यह केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि लोकतंत्र की विश्वसनीयता और पारदर्शिता को सुदृढ़ करने की दिशा में एक निर्णायक पहल है।

पुनरीक्षण की आवश्यकता

मतदाता सूची में सुधार केवल चुनाव आयोग का दायित्व नहीं, बल्कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और विश्वसनीय चुनावों के लिए यह एक अनिवार्य शर्त है।

जनसांख्यिकीय बदलाव- देश के भीतर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा या अन्य कारणों से अपने निवास स्थान बदलते रहते हैं। इससे कई नाम पुराने पते पर बने रह जाते हैं, जिससे सूची की प्रासंगिकता घटती है।

- **मृतकों के नाम-** समय-समय पर यह पाया गया है कि मृत व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में बने रहते हैं, जिससे उसकी सटीकता और विश्वसनीयता प्रभावित होती है।
- **नए पात्र नागरिकों का समावेश-** हर पात्र नागरिक को मतदाता सूची में शामिल करना आवश्यक है ताकि कोई भी व्यक्ति अपने मताधिकार से वंचित न रह जाए। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो।

ध्यान देने योग्य है कि ऐसा व्यापक पुनरीक्षण लगभग दो दशक पहले हुआ था। इतना लंबा अंतराल लोकतंत्र की निरंतरता और सटीकता के लिए उचित नहीं माना जा सकता। अतः यह पहल समय की माँग है।

पारदर्शिता और मजबूती की दिशा में

निर्वाचन आयोग का यह कदम न केवल मतदाता सूची को अद्यतन करेगा, बल्कि पूरी चुनावी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और विश्वसनीय बनाएगा।

- **त्रुटियों का सुधार-** मौजूदा सूचियों में मौजूद त्रुटियों को सुधारने का यह सुनहरा अवसर है।
- **नए मतदाताओं की भागीदारी-** विशेष रूप से युवाओं और महिलाओं के लिए यह पुनरीक्षण लोकतंत्र में उनकी सहभागिता को सुनिश्चित करने का अवसर है।
- **तकनीकी सहयोग-** आज उपलब्ध आधुनिक तकनीकी साधनों — जैसे डिजिटाइजेशन, ऑनलाइन सत्यापन, और डेटा एनालिटिक्स — के उपयोग से यह प्रक्रिया पहले से कहीं अधिक तेज, सटीक और पारदर्शी हो गई है।

राजनीतिक विरोधाभास

यह एक विडंबना है कि जहाँ राजनीतिक दल अक्सर मतदाता सूचियों में गड़बड़ियों की शिकायत करते हैं, वहीं उनके सुधार और पुनरीक्षण की प्रक्रिया पर भी आपत्ति जताते हैं। यह दोहरा रवैया लोकतांत्रिक भावना के अनुरूप नहीं कहा जा सकता। किसी भी दल या व्यक्ति का वास्तविक दायित्व यह होना चाहिए कि वह मतदाता सूची की शुद्धता और विश्वसनीयता में सहयोग करे, न कि उसके सुधार में बाधा बने।

चुनाव आयोग का यह कदम केवल एक तकनीकी या प्रशासनिक कार्यवाही नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की मूल आत्मा को सशक्त करने वाला कदम है। यह सुनिश्चित करेगा कि हर मतदाता की आवाज़ सही रूप में दर्ज हो, और कोई भी नागरिक लोकतंत्र की मुख्यधारा से बाहर न रह जाए।

इसलिए, मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण की इस प्रक्रिया का खुले मन से स्वागत किया जाना चाहिए। यह न केवल हमारी चुनावी प्रणाली को अधिक सटीक और पारदर्शी बनाएगा, बल्कि हमारे लोकतंत्र को और अधिक सशक्त, सहभागी और जनोन्मुख बनाएगा।

■ रविकांत जायसवाल, शिवम विहार, अमलीडीह , रायपुर (छ.ग.)

आयुर्वेद पर मगरूर आधुनिकता का हमला

“ भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था एक बार फिर एक अजीब और खतरनाक बहस के बीच खड़ी है। ताज़ा खबर ने माहौल गर्माया– कुछ निजी अस्पताल पैसा बचाने के लिए [illegible] डॉक्टरों की जगह [illegible] डॉक्टरों से इलाज करा रहे हैं। खबर ऐसे प्रस्तुत की गई, जैसे यह कोई धोखा, अपराध या लापरवाही हो। ”

लेकिन असल सवाल यह है- क्या यह समस्या BAMS डॉक्टरों की योग्यता है या निजी अस्पतालों की व्यावसायिक मानसिकता?

बात सिर्फ एक खबर की नहीं है, बल्कि उस मानसिक प्रवृत्ति की है जो भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति—आयुर्वेद—को नीचा दिखाने में आनंद लेती है। आज स्थिति यह है कि निजी अस्पतालों की एक लॉबी खुद को चिकित्सा जगत का ठेकेदार समझ बैठी है। उन्हें लगता है कि डॉक्टर वही है, जिसकी डिग्री वे मानें; बाकी सब तो बस व्यवस्था की भीड़ हैं। यही कारण है कि वे साढ़े चार साल की कठोर पढ़ाई, एक साल की क्लिनिकल इंटर्नशिप, और जीवनभर की सेवा करने वाले आयुर्वेदिक डॉक्टरों को 'झोला-छाप' कहने की हिमाकत करते हैं।

यह न सिर्फ अज्ञान है—यह अहंकार का चरम है।

आयुर्वेदिक डॉक्टर- झोला-छाप नहीं, भारतीय स्वास्थ्य तंत्र की रीढ़

जो लोग आयुर्वेदिक डॉक्टरों की डिग्री को हल्के में लेते हैं, वे शायद यह भी नहीं जानते कि BAMS की पढ़ाई में— Anatomy, Physiology, Pathology, फार्माकोलॉजी, मेडिकल एथिक्स, इमरजेंसी प्राइमरी केयर सब कुछ उतनी ही गंभीरता से पढ़ाया जाता है, जितना किसी भी आधुनिक चिकित्सा प्रणाली में। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि भारत की असल स्वास्थ्य सेवा—विशेषकर गांवों, कस्बों और छोटे शहरों में—इन्हीं आयुर्वेदिक डॉक्टरों के कंधों पर टिकी है।

जहां बड़े-बड़े MBBS डॉक्टर जाना भी नहीं चाहते, वहीं आयुर्वेदिक डॉक्टर वर्षों से-रात-दिन रोगियों को राहत देते हैं, कम संसाधनों में इलाज करते हैं, आपात स्थितियों में प्राथमिक उपचार संभालते हैं, स्वास्थ्य जागरूकता फैलाते हैं। क्या यह 'झोला-छाप' का काम है? या यह समाज की वह नींव है, जिसे देखने के लिए नज़रों में संवेदनशीलता चाहिए?

असली झोला-छाप कौन?

असली समस्या यह है कि जिन लोगों ने आयुर्वेद की एक औषधि का नाम तक नहीं पढ़ा, जो भारतीय चिकित्सा पद्धति को मात्र 'नॉन-एलोपैथिक' कहकर खारिज कर देते हैं, जो डॉक्टरों को योग्यता से नहीं, लॉबी से परिभाषित करते हैं— वे आयुर्वेदिक डॉक्टरों की योग्यता पर उंगली उठा रहे हैं। और दुर्भाग्य यह कि यह बयानबाजी सिर्फ अज्ञान का नहीं, बल्कि एक छिपे हुए व्यावसायिक एजेंडा का हिस्सा है।

जब निजी अस्पताल नियम तोड़ते हैं, जब वे डॉक्टरों को सिर्फ लागत और लाभ के समीकरण में तौलते हैं, तब दोष आयुर्वेदिक डॉक्टरों पर डालकर अपनी नैतिक जिम्मेदारी से बचना आसान होता है।

भारत की चिकित्सा परंपरा का अपमान

आयुर्वेद को 'झोला-छाप' कहना सिर्फ एक डॉक्टर का अपमान नहीं- यह भारत की हजारों साल पुरानी ज्ञान-परंपरा पर आघात है। यह उसी परंपरा का अनादर है जिसने- शल्य चिकित्सा की नींव रखी, रोग निदान की जटिल विधियाँ विकसित कीं, औषधियों की प्राकृतिक श्रेणी बनाई और संपूर्ण स्वास्थ्य—शरीर, मन, प्राण—की अवधारणा दी, आयुर्वेद कोई वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति नहीं है। यह भारत की मूल चिकित्सा पद्धति है। इसका अपमान करना न सिर्फ एक पेशे का, बल्कि इस सभ्यता की आत्मा का अपमान है। अब समय है—सम्मान लौटाने का।

आज आवश्यक यह है कि- आयुर्वेदिक डॉक्टरों को 'झोला-छाप' कहकर अपमानित करना बंद हो। सिस्टम यह स्वीकार करे कि ग्रामीण भारत का स्वास्थ्य आयुर्वेद पर आधारित है। सरकार, मीडिया और मेडिकल संस्थान आयुर्वेदिक डॉक्टरों को बराबरी का सम्मान दें।

निजी अस्पताल अपनी व्यावसायिक खामियों को छिपाने के लिए अन्य पद्धतियों को दोष न दें। इस देश का स्वास्थ्य तंत्र बहुलतावादी है—एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी—सभी मिलकर इसे पूर्ण बनाते हैं। एक को नीचा दिखाकर दूसरा ऊपर नहीं जाता; बस स्वास्थ्य व्यवस्था कमजोर पड़ती है।

आयुर्वेदिक डॉक्टरों को 'झोला-छाप' कहने वाले वास्तव में 'ज्ञान-छाप' हैं— क्योंकि वे न आयुर्वेद समझते हैं, न भारतीय चिकित्सा परंपरा, और न ही इस देश की वास्तविक स्वास्थ्य जरूरतें।

सच्चाई साफ है—भारत की जनता आज भी उतनी ही गर्मजोशी से आयुर्वेद पर विश्वास करती है, जितनी सदियों पहले करती थी।

अब जिम्मेदारी हमारी है— कि इस परंपरा का सम्मान लौटाएँ,और उन डॉक्टरों को उनका गौरव वापस दें जो मौन रहते हैं, पर सेवा में कभी पीछे नहीं हटते।

आधुनिक इलाज और होलिस्टिक वैलनेस– अब एक साथ

आज का युग यह स्पष्ट कर चुका है कि केवल बीमारी को समझना पर्याप्त नहीं है; मानव को उसके चरम स्वास्थ्य, ऊर्जा और वैलनेस की ओर ले जाने के लिए सालूटोजेनेसिस ही भविष्य का मार्ग है।

डॉ अनिल गुप्ता
फाउंडर पॉजिटिव हेल्थ जोन
डायरेक्टर श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल, रायपुर

स्वास्थ्य को समझने के दो बड़े मार्ग हैं— पैथोजेनेसिस और सालूटोजेनेसिस।

एक बीमारी की जड़ों में उतरता है, दूसरा स्वास्थ्य की जड़ों में। एक 'रोग' को खोजता है, दूसरा 'जीवन-ऊर्जा' को।

आज का युग यह स्पष्ट कर चुका है कि केवल बीमारी को समझना पर्याप्त नहीं है; मानव को उसके चरम स्वास्थ्य, ऊर्जा और वैलनेस की ओर ले जाने के लिए सालूटोजेनेसिस ही भविष्य का मार्ग है।

पैथोजेनेसिस- आधुनिक चिकित्सा की नींव—पर यात्रा का आधा हिस्सा। वर्तमान मेडिकल एवं हेल्थकेयर सिस्टम लगभग पूर्णतः पैथोजेनेसिस आधारित है। और यह आवश्यक भी है।

पैथोजेनेसिस पूछता है- बीमारी क्यों होती है?

यही दृष्टिकोण हमें देता है-

संक्रमण का उपचार, सर्जरी, ICU और आपात चिकित्सा, दवाएँ, एविडेंस-आधारित प्रोटोकॉल।

यहाँ कोई संदेह नहीं— पैथोजेनेसिस ने लाखों जीवन बचाए हैं। और आधुनिक चिकित्सा की रीढ़ यही है। लेकिन, यह दृष्टि एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात को नहीं छूती-

'मनुष्य केवल बीमारी नहीं है। वह जीवन है।'

पैथोजेनेसिस यह बताता है कि बीमारी कैसे नियंत्रित हो, पर यह नहीं बताता कि व्यक्ति कैसे- ऊर्जावान, मानसिक रूप से संतुलित, भावनात्मक रूप से स्थिर और आध्यात्मिक रूप से जाग्रत बने।

यहीं से आगे बढ़ता है सालूटोजेनेसिस।

सालूटोजेनेसिस- भविष्य की हेल्थकेयर—रोग से आगे, जीवन की ओर सालूटोजेनेसिस एक सरल, पर गहरा प्रश्न पूछता है-

'लोग कठिनाइयों, तनाव और चुनौतियों के बावजूद स्वस्थ कैसे रह लेते हैं?'

इस मॉडल के अनुसार— स्वास्थ्य एक स्थिर बिंदु नहीं, बल्कि एक निरंतर यात्रा (continuum) है।

मनुष्य बीमारी और स्वास्थ्य के बीच लगातार गतिमान है- और उचित परिस्थितियाँ मिल जाएँ, तो शरीर और मन स्वास्थ्य की ओर स्वयं बढ़ते हैं।

यह मॉडल केंद्रित है—हीलिंग क्षमता

■ Resilience (लचीलापन) ■ उद्देश्यपूर्ण जीवन ■ मन-शरीर संबंध ■ जीवनशैली ■ भावनात्मक संतुलन ■ सामाजिक समर्थन ■ प्राकृतिक उपचार-शक्ति।

यही सालूटोजेनेसिस की शक्ति है— यह रोग नहीं, स्वास्थ्य को जन्म देता है।

Health Spectrum -5 से +5 तक की यात्रा

डॉ. अनिल गुप्ता स्वास्थ्य को एक रेखा में समझाते हैं:- -5 से 0- बीमारी की ओर झुकाव (Pathogenesis Zone)

* बीमारी * थकान * तनाव * अव्यवस्था * मेटाबॉलिक असंतुलन।

यहाँ पैथोजेनेसिस जीवन बचाता है।

दवाओं, सर्जरी, विज्ञान और इलाज की जरूरत होती है। यह अनिवार्य है—पर यही स्वास्थ्य नहीं।

स्वास्थ्य, ऊर्जा और उत्कर्ष (Salutogenesis Zone)

* बेहतर नींद * बेहतर पाचन * स्पष्टता * उत्साह * भावनात्मक संतुलन * आध्यात्मिक जागरूकता * उद्देश्यपूर्ण जीवन

यह वह क्षेत्र है जहाँ व्यक्ति केवल 'रोग-मुक्त' नहीं— बल्कि जीवन-पूर्ण होता है।

वर्तमान चिकित्सा की सीमा – और भविष्य की दिशा

डॉ. अनिल गुप्ता स्पष्ट कहते हैं- आज का मेडिकल सिस्टम शरीर को बचा सकता है, लेकिन मन, भावनाओं और ऊर्जा को नहीं

SPECTRUM OF HEALTH

संभाल सकता। और जब तक ये तीन नहीं संभलते—पूर्ण स्वास्थ्य संभव नहीं।

आधुनिक चिकित्सा बीमारी रोकने के लिए आवश्यक है। लेकिन स्वास्थ्य के निर्माण के लिए भविष्य सालूटोजेनेसिस का है।

सालूटोजेनेसिस के तीन मूल स्तंभ

(Antonovsky Model)

* **समझने की क्षमता (Comprehensibility)**
हम अपने शरीर, मन और भावनाओं को समझें। स्वास्थ्य जागरूकता बढ़े।

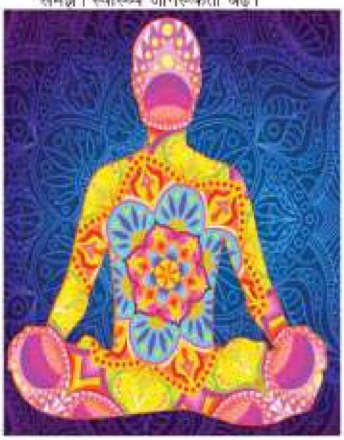

> "आज की हेल्थकेयर चुनौती का समाधान पैथोजेनेसिस और सालूटोजेनेसिस के समन्वय में है। पिछले 15 वर्षों की रिसर्च से मैंने Quantum Veda Model विकसित किया है—जहाँ आधुनिक चिकित्सा की वैज्ञानिक शक्ति और जीवन-ऊर्जा आधारित वैलनेस एकीकृत होकर समग्र, स्थायी और उद्देश्यपूर्ण स्वास्थ्य का नया मार्ग बनाते हैं।"
>
> **- डॉ. अनिल गुप्ता**

* **नियंत्रित करने की क्षमता (Manageability)**
हमारे पास वह ऊर्जा, साधन और समर्थन हो जिससे हम स्वास्थ्य संभाल सकें।
* **जीवन में अर्थ** (Meaningfulness)
जिस व्यक्ति के जीवन में उद्देश्य है, उसका स्वास्थ्य स्वाभाविक रूप से बेहतर होता है।

डॉ. गुप्ता कहते हैं— "Meaningfulness is medicine." उद्देश्य ही असली पोषण है।

Integrated Holistic Healthcare: दोनों का संगम

स्वास्थ्य का वास्तविक मॉडल वह है जहाँ पैथोजेनेसिस और सालूटोजेनेसिस दोनों मिलकर काम करें।

इसे डॉ. गुप्ता कहते हैं—इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थकेयर। इसमें शामिल हैं—

* Modern Medicine * Nutrition Science
* योग * ध्यान * प्राणायाम * माइंडफुलनेस * मानसिक स्वास्थ्य * सामाजिक और पर्यावरणीय स्वास्थ्य * आयुर्वेदिक सिद्धांत * लाइफस्टाइल मेडिसिन

यह मॉडल शरीर नहीं— मनुष्य को संपूर्णता में देखता है।

Positive Health Zone: नया भविष्य, नया दर्शन

डॉ. अनिल गुप्ता द्वारा प्रस्तावित Positive Health Zone, एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म और दर्शन है जहाँ— * बीमारी का इलाज भी है स्वास्थ्य का निर्माण भी।

* आधुनिक विज्ञान भी और शाश्वत ज्ञान भी * प्रिवेंशन भी और वैलनेस भी।

यहीं से शुरू होता है

Disease से Ease, Illness से Wellness और Survival से Thriving की यात्रा।

— पैथोजेनेसिस ज़रूरी है, पर सालूटोजेनेसिस भविष्य है।

आज मानवता के सामने नई दिशा स्पष्ट है—

* बीमारी रोकने के लिए पैथोजेनेसिस
* स्वास्थ्य बनाने के लिए सालूटोजेनेसिस
* और दोनों को मिलाने के लिए **Positive Health Zone**

उपचार से आगे, स्वास्थ्य से आगे, उत्कर्ष की ओर बढ़ने का समय आ गया है।

www.phzinfo.in
dranilinfo.com
9109185025
9109185028

कॉर्पोरेट वेलनेस

तनाव से ट्रांसफ़ॉर्मेशन तक

आज की कॉर्पोरेट दुनिया में सबसे बड़ा संकट तकनीक, टारगेट या टैलेंट की कमी नहीं है—सबसे बड़ा संकट है लगातार बढ़ता तनाव, अनियमित दिनचर्या, और लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर्स का विस्फोट।

आज हर कंपनी एक ही दर्द साझा कर रही है—गले और कमर का दर्द , ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, एंजायटी, स्क्रीन फ़टीग, लो एनर्जी, एंड बर्नआउट।

और हर कर्मचारी की इच्छा भी स्पष्ट है—कम तनाव, अच्छी नींद, अधिक ऊर्जा और इमोशनल स्टेबिलिटी ।

यही दो ज़रूरतें मिलकर एक नए मॉडल की माँग पैदा करती हैं—

सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं, बल्कि टोटल हीलिंग।

सिर्फ दवाइयाँ नहीं, बल्कि रूट कॉज़ रेज़ोल्यूशन।

सिर्फ फिटनेस नहीं, बल्कि होलिस्टिक वेलनेस।

कॉर्पोरेट की चुनौती

कंपनियाँ चाहती हैं—

प्रोडक्टिविटी बढ़े

सिक लीव कम हों

टीमें अधिक फोकस्ड और खुश रहें

ऑफिस माहौल सकारात्मक बने

एम्प्लॉयी रिलेशन मजबूत हो

ब्रांड वैल्यू बढ़े

लेकिन जब कर्मचारी थकान, तनाव और भीतर-ही-भीतर बढ़ते असंतुलन से गुजरते हैं, तब यह सब लक्ष्य केवल कागज़ पर ही रह जाते हैं।

कर्मचारियों की चुनौती

हर कर्मचारी चाहता है—

तनाव कम हो

क्रॉनिक डिज़ीज़ का जोखिम घटे

एनर्जी लेवल स्टेबल रहे

मन शांत और क्लियर रहे

नींद गहरी और रिस्टोरेटिव हो

इमोशनल बैलेंस मजबूत हो

स्पष्ट है—दोनों की ज़रूरतें एक-दूसरे की पूरक हैं। और इन दोनों के बीच पुल बनकर आता है—

Positive Health Zone का **Corporate Wellness Program** ,जो देता है रूट कॉज़ आधारित समग्र समाधान।

पॉज़िटिव हेल्थ ज़ोन का विश्वास स्पष्ट है—

'बीमारी नहीं, पूरे इंसान को देखो।'

हम सिर्फ लक्षणों को नहीं, उनके मूल कारणों को पहचानते हैं। हम शरीर, मन और ऊर्जा तीनों स्तरों पर संतुलन बनाते हैं, जिससे कर्मचारी न सिर्फ स्वस्थ हों, बल्कि ट्रांसफ़ॉर्म हों।

कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएँ

- **रूट कॉज़ हीलिंग और लाइफ़स्टाइल करेक्शन**

हर व्यक्ति के स्ट्रेस पैटर्न, बायोलॉजिकल रिद्म, स्लीप साइकिल, हॉर्मोनल डिसबैलेंस और ऊर्जा प्रवाह को समझकर व्यावहारिक समाधान दिए जाते हैं।

- **आधुनिक विज्ञान और प्राचीन वेद का संगम**

हम उपयोग करते हैं—

GDV Bio-Well Scan , Veda Pulse Analysis , Energy Mapping , Organ Function Assessment , Mental Detox & Healing , Body Detox Zone

इन तकनीकों से न सिर्फ शरीर बल्कि मन और ऊर्जा की वास्तविक स्थिति सामने आती है।

- **Mind–Body Alignment & Personalized Care**

प्रत्येक कर्मचारी को उनके अनुकूल — डाइट प्लान , माइंड बैलेंसिंग तकनीक , ब्रीदिंग × मेडिटेशन प्रोटोकॉल , डिटॉक्स रूटीन , इमोशनल रीकैलिब्रेशन दिया जाता है, ताकि वे भीतर से रीसेट हो सकें।

परिणाम : बर्नआउट से बैलेंस तक

इस कार्यक्रम के बाद व्यक्ति—

- **तनाव- से** calmness
- **कमज़ोरी-** vitality
- **कन्फ्यूज़न** clarity
- **बेचैनी** emotional stability
- **कम फोकस - sharp productivity के रास्ते पर बढ़ता है।**

कंपनी को मिलता है—

सतत प्रदर्शन, सकारात्मक माहौल और मजबूत वर्क कल्चर। यही है असली Holistic Wllness. दोस्तों Positive Health Zone का Corporate Wellness Program किसी सत्र या वर्कशॉप का नाम नहीं है—यह एक Rejuvenation Journey है, जहाँ हर व्यक्ति खुद के सर्वश्रेष्ठ संस्करण की ओर बढ़ता है।

यदि आपका संगठन सिर्फ वर्कफ़ोर्स नहीं, बल्कि हेल्दी, एनर्जेटिक और इमोशनली सस्टेन्ड टीम बनाना चाहता है तो पॉज़िटिव हेल्थ ज़ोन आपका स्वागत करता है—

एक ऐसी यात्रा में जहाँ बदलाव सिर्फ शरीर में नहीं, पूरे जीवन में दिखता है।

9109185025
8817194979

मरने की कला सीखना जरुरी है

हम जीवन जीने की कला पर सैकड़ों किताबें लिखते हैं, कोर्स बनाते हैं, प्रवचन सुनते हैं। लेकिन एक कला ऐसी है जिस पर लगभग मौन छाया रहता है— मरने की कला।

यह कला किसी सन्यास का उपदेश नहीं है, न ही यह मृत्यु को बुलाने की कोई निराशाजनक सोच। यह तो जीवन का सबसे परिपक्व अध्याय है— एक ऐसा अध्याय, जिसे केवल वही लोग लिख पाते हैं जिन्होंने जीवन को पूरी सजगता, जिम्मेदारी और प्रेम के साथ जिया हो।

हम अक्सर सहज, शांत और दर्दरहित मृत्यु को किसी चमत्कार की तरह देखते हैं। लेकिन सच यह है कि सरल मृत्यु कोई बाहरी चमत्कार नहीं; यह तो भीतर की अवस्था है।

आसान मृत्यु कोई चमत्कार नहीं-

हम अक्सर सहज, शांत और दर्दरहित मृत्यु को किसी चमत्कार की तरह देखते हैं। लेकिन सच यह है कि सरल मृत्यु कोई बाहरी चमत्कार नहीं; यह तो भीतर की अवस्था है।

जब मन में कोई अधूरापन न बचे, जब आत्मा यह कह सके— 'जो करना था, कर लिया। जो कहना था, कह दिया। जो छोड़ना था, छोड़ दिया।' तब मृत्यु कठोर नहीं लगती। वह बस एक अंतिम विश्राम बन जाती है।

ऐसे लोगों के शरीर भले ही मौन हो जाएं, लेकिन उनकी आत्मा मुस्कुराती है— एक संतोष की मुस्कान, एक पूर्णता की सुगंध के साथ।

कष्ट उसी को होता है जो जीवन को पकड़े बैठा है।

मृत्यु का भय, दर्द और संघर्ष ज्यादातर उन लोगों को सताता है जो जीवन से अत्यधिक चिपके रहते हैं।

- अधूरी महत्वाकांक्षाएँ
- अपूर्ण इच्छाएँ
- टूटे संबंधों के बोझ
- क्षमा न कर पाने का कठोरपन
- और 'कुछ और' पाने की अंतहीन ललक

ये सभी मिलकर मृत्यु को कठिन बना देते हैं। जो जीवन को हथियाने की मानसिकता में रहा हो, उसे छोड़ना स्वाभाविक रूप से असहनीय लगता है। वह मृत्यु नहीं, बल्कि हानि देखता है- और इसलिए मृत्यु दुखद, भयपूर्ण और अव्यवस्थित लगती है।

जीते-जी मरना ही मरने की सबसे बड़ी कला है

मरने की सच्ची कला यह है कि इंसान जीते-जी कुछ मृत्युएँ स्वीकार कर ले।

- अहंकार को धीरे-धीरे मरने दे
- पुराने दु:खों को दफना दे
- आसक्तियों की पकड़ ढीली कर दे
- हर दिन थोड़ा-थोड़ा हल्का होता जाए

जो अपने भीतर इन छोटी-छोटी मृत्यु को स्वीकार लेता है, उसके लिए अंतिम मृत्यु कोई दुर्घटना नहीं, कोई भयभीत करने वाली घटना नहीं- बल्कि एक स्वाभाविक, सहज और शांत यात्रा है।

ऐसा व्यक्ति मृत्यु से लड़ता नहीं, वह उससे संवाद करता है। वह उसे विरोध नहीं देता, बल्कि उसका सम्मान करता है।

सबसे शांत मृत्यु किसे मिलती है?

समाज में प्रचलित धारणा यह है कि मृत्यु सबके लिए समान है। लेकिन वास्तविकता इससे कहीं सूक्ष्म है।

सबसे शांत, सहज और दर्दरहित मृत्यु उन्हीं को मिलती है—

- जो जीवन से संतुष्ट हैं
- जिन्होंने दूसरों को दुख नहीं पहुँचाया
- जिन्होंने माफ़ करना और क्षमा माँगना सीखा
- जिन्होंने संबंधों को बोझ नहीं, बल्कि सौभाग्य माना
- जो समय को प्रतिद्वंद्वी नहीं, मार्गदर्शक समझते हैं

ऐसे लोग मृत्यु में अंधकार नहीं देखते। उनके लिए मृत्यु एक नया उजाला है- एक ऐसी सुबह, जो रात के पार खुलती है।

अंत में कुछ प्रश्न-

- क्या मरने की कला जीने की कला से ही शुरू नहीं होती?
- क्या जिसने जीवन में छोड़ना सीखा है, वही सबसे सहज मृत्यु प्राप्त कर सकता है?
- क्या संतोष से भरा जीवन मृत्यु के अंधकार को भी प्रकाश में बदल देता है?

इन प्रश्नों में ही जीवन का सार छिपा है, और मृत्यु का रहस्य भी।

जीवन की असली पूर्णता तब होती है जब इंसान मरते समय डर नहीं, धन्यवाद लेकर जाता है।

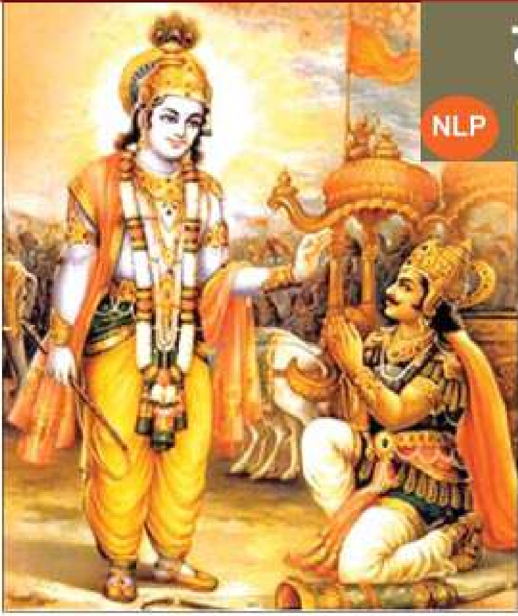

मन का युद्ध भूमि

NLP

।। श्रीमद्‌भगवद्‌गीता ।।

नरेन्द्र पाण्डेय

गतांक से आगे

श्लोक 2

संजय उवाच –

दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा।
आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत्॥

संजय बोले -' पांडवों की सेना को युद्ध के लिए सज्जित देखकर, राजा दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और बोला।'

दुर्योधन ने जैसे ही पांडवों की सेना को व्यवस्थित 'संगठित' और 'तैयार' देखकर दुर्योधन के मन में हलचल मचती है। वह सीधे गुरु द्रोण के पास जाता है। यह कोई संयोग नहीं है। इसके पीछे उसकी असुरक्षा है, एक डर है जो उसकी सतर्कता के पीछे छिपा हुआ है। यह कोई सलाह लेने की बात नहीं - यह एक डरे हुए मन का सहारा ढूंढना है। जब हम किसी चुनौती को देखते हैं, तो या तो उसका सामना करते हैं, या किसी बड़े सहारे की शरण में जाते हैं। दुर्योधन ने दूसरा रास्ता चुना।

वह राजा है, सेनापति है, फिर भी वह नेतृत्व नहीं कर रहा -वह प्रतिक्रिया दे रहा है। यह वही मनोदशा है जो आज की दुनिया में भी दिखती है। जब हम किसी चुनौती को देखते हैं, तो या तो उसका सामना करते हैं, या किसी बड़े सहारे की शरण लेते हैं। जब कोई अधिकारी या लीडर किसी प्रतिस्पर्धा से डरता है, तो वह अपने बॉस या मेंटर के पास जाकर अप्रत्यक्ष रूप से पुष्टि माँगता है - 'देखिए न, वो कितने ताकतवर हैं!' दुर्योधन यहाँ अपने गुरु से "validation" (पुष्टि) चाहता है -' गुरुजी, देखिए न, वो कितने ताकतवर लग रहे हैं!' यह वही मनोदशा है जो आज के नेताओं या प्रबंधकों में दिखती है।

एक सवाल

दुर्योधन के पास विशाल सेना है, शक्तिशाली योद्धा हैं, फिर भी वह डर क्यों रहा है? यह डर बाहर की ताकत से नहीं, भीतर की कमजोरी से है। बाहर से ताकतवर दिखने वाला इंसान भी अगर भीतर से स्पष्ट नहीं है कि वह क्यों लड़ रहा है, तो वह डरता ही है। जब हमारा 'क्यों' (उद्देश्य) स्पष्ट नहीं होता, तो बाहर की हर शक्ति हमें डराती है।

हम भी अपने जीवन में ऐसा करते हैं। जब कोई सामने सफल दिखता है, तो हम सीधे टकराने के बजाय किसी से सलाह लेने भागते हैं। यह हमारी भीतरी उलझन की निशानी है।

श्लोक 3

पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूम्।
व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता॥

दुर्योधन बोला -आचार्य! देखिए पांडवों की इस विशाल सेना को, जो आपके ही शिष्य, द्रुपद के बेटे धृष्टद्युम्न ने सजाई है।

यहाँ दुर्योधन की भाषा में शिकायत और छिपा हुआ गुस्सा झलकता है। 'पश्य' (देखिए!) कोई साधारण आग्रह नहीं - यह एक भावनात्मक उकसावा है। दुर्योधन की बात साधारण नहीं है। 'पश्य' (देखिए) एक आज्ञा है, शिकायत है। वह कह रहा है - यह सब आपके ही कारण हुआ है। 'तव शिष्येण' (आपके शिष्य ने) कहकर वह द्रोणाचार्य को अपराध-बोध में डालना चाहता है। यह एक Blaming है। सामने वाले को दोष न देते हुए भी, शब्दों से जिम्मेदारी थोप देना। जैसे कोई कहे, 'आपने ही उसे सिखाया था, अब देखिए वो हमारे खिलाफ है।' दुर्योधन डर रहा है, और यह डर उसे दूसरों पर दोष मढ़ने को मजबूर कर रहा है।

उदाहरण के लिए, आज कोई बॉस अपने मैनेजर से कहे -इस टीम को आपने ही ट्रेन किया था न? अब देखिए कैसे काम कर रही है। यहाँ दोष सीधे नहीं दिया जाता, पर शब्दों से जिम्मेदारी थोप दी जाती है। दुर्योधन भी यही कर रहा है - वह डर रहा है, और अपने डर को गुरु पर डालना चाहता है।

हम भी ऐसा कई बार करते हैं। जब कोई हमारे खिलाफ खड़ा हो, तो हम कहते हैं -'आपने ही उसे बढ़ावा दिया था।' यह मन की वह युक्ति है जो अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए दूसरों को कठघरे में खड़ा करती है। **(क्रमशः)**

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री
छत्तीसगढ़ शासन

छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड की उपलब्धियां

- छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड का मुख्य उद्देश्य कृषकों को उनकी उपज का सही तौल, सही कीमत एवं समय पर भुगतान करना है।
- छत्तीसगढ़ राज्य में एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फण्ड योजना के अंतर्गत वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, शार्टिंग एवं ग्रेडिंग, प्राथमिक प्रसंस्करण इकाई, साइलोज, पैकेजिंग इकाई, रायजनिंग चेंबर, वैक्सिम प्लाट, दाल मिल, आटा मिल राईस मिल, कोल्ड प्रेस ऑइल मिल, आर्गेनिक इनपुट प्रोडक्शन, बायोस्टीकुलेन्ट, कुस्टम हायरिंग सेन्टर परियोजनाओं के लिए बिना बैंक गारण्टी के 2 करोड़ तक ऋण में प्रतिवर्ष 3% ब्याज दर में छुट है। यह आर्थिक सहायता अधिकतम 7 वर्षों की अवधि के लिए उपलब्ध होगी। अन्य योजनाओं में लाभ प्राप्त होने पर भी इस योजना का लाभ दिया जायेगा। यह योजना मार्च-2026 तक लागू रहेगा। राज्य में इस योजना के लाभ 1480 लाभार्थी प्राप्त कर चुके है।
- राज्य के कृषकों को कृषि उपज के अधिक मूल्य प्रदाय करने तथा नीलामी में पारदर्शिता के दृष्टिकोण से 20 मंडियों कमशः नवापारा, राजनांदगांव, कवर्धा, भाटापारा, कुरूद, रायपुर, दुर्ग, धमतरी, बिलासपुर, जगदलपुर, राजिम, बालोद, मुंगेली, रायगढ़, कांकेर, सरायपाली, बेमेतरा, कटघोरा, अंबिकापुर एवं जशपुर को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ी गई है।
- कृषकों की कृषि उपज के वैज्ञानिक ढंग से भंडारण हेतु प्रदेश के मंडी समितियों में 4 लाख 4 हजार मे. टन क्षमता के गोदाम निर्मित है।
- प्रदेश में बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़, धमतरी, पखांजूर, पत्थलगांव तथा उपमंडी धमधा में फल-सब्जी का क्रय विक्रय हो रहा है, इसके अतिरिक्त गण्डई, कुनकुरी तथा कुसमी में फल-सब्जी मंडी का निर्माण कार्य किया जा रहा है।
- गौ-सेवा आयोग को वृद्ध पशुओं की देखभाल तथा गौशालाओं के संरक्षण हेतु 2019-20 से अब तक 205.17 करोड़ का अनुदान दिया गया।
- ई-मंडी आनलाईन के माध्यम से सभी मंडियों के आवक-जावक, फसलों के मूल्य की जानकारी कृषकों एवं व्यापारियों को इस साफ्टवेयर के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही मंडी भाव एप के द्वारा अपने एण्ड्राइड मोबाईल पर राज्य के सभी मंडियों के सभी प्रकार के उपज का तिथिवार मूल्य देखा जा सकता है।

संवाद- 13520/1

छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड

सरदार वल्लभ भाई पटेल भवन, सेक्टर-24, क्याबांधा, अटल नगर, नवारायपुर-492018

www.phzinfo.com

Positive Health Zone

Integrated Holistic Health Care System

Unique Wellbeing Center

Holistic Healthcare Team

Our INTEGRATED SERVICES

Holistic Path Of Wellness & Wellbeing

1. **Personal Energy Blueprint at Quantum Veda Lab with Latest Quantum Devices-**

   Aura, Chakra, Biofield, Lifeforce Energy Analysis.

2. **Digital Nadi Parikshan Modern Nadi Veda Pulse -**

   Personality Analysis Body Type, Mind Type, Energy Type.

3. **Life Style Clinic**

   Personalised Diet Plan, Lifestyle Plan, Day Plan, Detox Plan as per your Quantum Analysis.

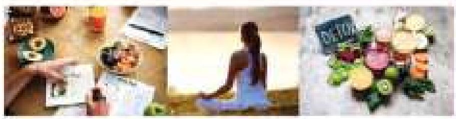

4. **Body Detox & Rejuvenation with Kerala Ayurveda Panchkarma.**

5. **Mind Detox & Stress Management with NLP & Counselling.**

6. **Inner Alingment, Chakra Balancing with PNP Meditation.**

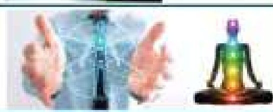

Get In Touch
9109105020, 9109105025

A-41, Amrapali Society,
Near Ganga Diagnostics, Raipur, Chhattisgarh

www.phzinfo.com